वर्ष 13 • अंक 44 • 8 पृष्ठ
• मूल्य 5 रुपये

शनिवार 11 अप्रैल 2020

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

▶▶ पृष्ठ 2

इंडिगो आधी क्षमता के साथ शुरू करेगी परिचालन

टी वी नरेंद्रन ▶▶ पृष्ठ 3

भारत में लंबे समय तक लॉकडाउन सहने की क्षमता

एक नज़र

शीर्ष तेल उत्पादक देश उत्पादन में कटौती पर सहमत

तेल उत्पादक देशों के संगठन ओपेक ने शुक्रवार को कहा कि मैक्सिको को छोड़कर प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने मई और जून में उत्पादन में प्रतिदिन एक करोड़ बैरल की कटौती करने पर सहमति व्यक्त की है। ओपेक और रूस सहित अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देश कीमतों में भारी गिरावट रोकने के लिए गहन वार्ता के बाद इस नतीजे पर पहुंचे। इस बीच, मैक्सिको ने कहा है कि वह उत्पादन में प्रति दिन 1 लाख बैरल कटौती करेगा। ओपेक ने कहा कि तेल उत्पादन में जुलाई से दिसंबर तक 80 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती करने के समझौते पर सहमति हुई है। इस बीच, ओपेक के सदस्य देश मेक्सिको ने कहा कि उत्पादन में कटौती पर अमेरिकी के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के साथ उनका समझौता हुआ है। कोरोनावायरस संकट के बीच शुक्रवार को जी-20 समूह देशों की बैठक भी आयोजित हुई।

जी-20 के वित्त मंत्रियों की बैठक 15 अप्रैल को

जी-20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक 15 अप्रैल को होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये होने वाली इस बैठक में कोविड-19 संकट के बाद अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक से 15 दिन पहले यानी 31 मार्च को भी वित्त मंत्रियों और गवर्नरों की बैठक हुई थी। एक अधिकारी ने कहा कि 15 अप्रैल की बैठक 31 मार्च से आगे की बैठक है।

एफसीआई के अधिकारियों को 35 लाख का बीमा

केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने शुक्रवार को भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के अधिकारियों एवं श्रमिकों को प्रति व्यक्ति 35 लाख रुपये का जीवन बीमा देने की घोषणा की। पासवान ने कहा कि 24 मार्च को लॉकडाउन शुरू होने के बाद अगले छह महीने की अवधि के बाद अधिकारियों या श्रमिकों की मृत्यु होने पर उन्हें 35 लाख रुपये दिए जाएंगे। एफसीआई एक सरकारी एजेंसी है, जो किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्न खरीदती है और सस्ती दरों पर देश में राशनकार्ड धारकों को बेचती है।

चरणबद्ध तरीके से हवाई यातायात की सिफारिश

हवाईअड्डों की सुरक्षा संभालने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने चरणबद्ध तरीके से हवाई यातायात शुरू करने की सिफारिश की है। इसने कारोबार निरंतरता योजना के तहत अपनी यह सिफारिश नागरिक विमानन मंत्रालय को सौंपी है। सीआईएसएफ ने हवाईअड्डों पर भीड़ कम करने के लिए उड़ान से दो घंटे पहले चेक-इन काउंटर बंद करने का सुझाव दिया है। उसने यात्रियों के बीच दूरी भी बरतने की सलाह दी है। पृष्ठ 2

एडीबी से भारत को 2.2 अरब डॉलर का आश्वासन

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार करने, देशबंदी के कारण कठिन दौर से गुजर रहे गरीबों और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों की मदद के लिए भारत को 2.2 अरब डॉलर (करीब 16,000 करोड़ रुपये) की मदद का आश्वासन दिया है। एडीबी के अध्यक्ष मासतसुगु असाकावा ने शुक्रवार को कहा कि एडीबी भारत की सहायता के लिए प्रतिबद्ध है। पृष्ठ 4

त्यापार गोष्ठी

कोरोना की मार से कैसे बचें छोटे उद्योग?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201
या फिर ई-मेल करें goshthi@bsmail.in
अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

क्या सरकार को बढ़ानी चाहिए लॉकडाउन की अवधि

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या कोविड-19 संकट के बाद जल्द उबर पाएगी देश की अर्थव्यवस्था	
हां	28.57%
नहीं	71.43%

लॉकडाउन फैसला केंद्र पर

प्रधानमंत्री राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शनिवार को करेंगे इस मुद्दे पर बैठक

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल

अधिकतर बड़े राज्यों ने आज देर शाम सुझाव दिया कि लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद आगे बढ़ाया जाना चहिए और संभव हो तो इसे माह के अंत तक जारी रखना चाहिए। राज्यों ने लॉकडाउन पर अंतिम निर्णय लेने की जिम्मेदारी अब केंद्र के पाले में डाल दी है, जो इसे हटाने, बढ़ाने या कुछ आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के बारे में निर्णय लेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को इस मसले पर चर्चा के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में वह राष्ट्र को एक बार फिर संबोधित कर सकते हैं और आगे की जानकारी दे सकते हैं।

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ नीति निर्माता ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों के साथ 'ग्रीन जोन' चिह्नित करने के लिए काम कर रही है, जहां औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। सरकार का विचार है कि लॉकडाउन को व्यापक तौर पर आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

केंद्र ने गृह सचिव और उपभोक्ता मामलों के सचिव के माध्यम से राज्यों को संदेश भेजा है कि आवश्यक वस्तुओं के घटते स्टॉक को बढ़ाने के लिए सीमित दायरे में औद्योगिक गतिविधियां, कारखाने और वेयरहाउस को चालू करने की जरूरत है और इसके लिए श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करानी होगी।

हालांकि अधिकांश राज्यों ने अपने सुझाव संबंधित समितियों को दे दिए हैं, वहीं केरल सरकार के कार्यबल ने लॉकडाउन से निकलने के लिए 36 पृष्ठ का तीन स्तरीय योजना लेकर आई है। आने वालों हफ्तों में राज्य इसका पालन कर सकता है।

केंद्र के साथ ही उद्योग संगठन भी सीमित दायरे में आर्थिक गतिविधियां शुरू करना चाहते हैं। हालांकि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मोदी सरकार की ओर से आवंटित कम धनराशि को लेकर राज्य निराश हैं।

इस बीच पंजाब मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री की घोषणा का इंतजार किए बिना लॉकडाउन को 1 मई तक बढ़ा दिया है। ओडिशा के बाद ऐसा करने वाला पंजाब दूसरा राज्य है। इससे पहले गुरुवार को ओडिशा ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने की घोषणा की थी। हालांकि पंजाब सरकार ने जरूरत पड़ने पर फसलों की कटाई और गेहूं की खरीद के लिए लॉकडाउन में कुछ ढील देने के संकेत दिए हैं।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रेल और हवाई सेवा बहाल करना केंद्र का विशेषाधिकार है लेकिन वह अभी अपने राज्य में अंतरराज्यीय सड़क परिवहन की अनुमति नहीं दे सकते हैं। भाजपा शासित कर्नाटक ने भी लॉकडाउन हटाने का विरोध किया है जबकि महाराष्ट्र भी अभी लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं है क्योंकि ऐसा करने से उसके शहरी इलाकों में मरीजों की संख्या में भारी तेजी आ सकती है।

माना जा रहा है कि शनिवार को होने वाली बैठक में गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री फंड की कमी का मामला उठा सकते हैं। शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि कोविड-19 से लड़ने के लिए राज्यों को दिया गया 15,000 करोड़ रुपये का फंड पर्याप्त नहीं है। ■ शेष पृष्ठ 8

कोरोना मामले

भारत	
कुल	6,761
सक्रिय मामले	6,039
ठीक हुए	515
मौत	206

विश्व	
कुल	1,633,452
मौत	98,379

नोटः कुल मामलों में एक पलायन किया मरीज भी शामिल है।
स्रोतः स्वास्थ्य मंत्रालय, जॉन हॉपकिंस कोरोनावायरस रिसोर्स सेंटर

चारों तरफ माल का लगा अंबार

अदिति दिवेकर, अरिंदम मजूमदार, अनीश फडणीस और शाइन जैकब
मुंबई/नई दिल्ली, 10 अप्रैल

- लॉकडाउन की वजह से माल नहीं उठा रहे आयातक
- कई बंदरगाहों पर माल रखने में आ रही दिक्कत
- हवाईअड्डों पर भी भारी तादाद में माल जमा
- हवाईअड्डों पर करीब 3,000 टन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यरेबल्स और वाहन पुर्जों का जखीरा

हवाई मार्ग और रेलवे से मालवहन तथा बंदरगाहों पर कार्गो की आवाजाही को लेकर लॉकडाउन में किसी तरह की बंदिश नहीं है, लेकिन श्रमिकों की कमी और परिवहन सुविधाओं के अभाव में हवाई अड्डों, बंदरगाहों और रेलवे स्टेशनों पर कार्गो अटके पड़े हैं। इनके मालिक अपने माल को वहां से उठा नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही जरूरी और गैर-जरूरी सामान को लेकर अस्पष्टता के कारण भी कार्गो को खाली करने में समस्या आ रही है। हवाई अड्डों से कार्गो उठाने में देरी को लेकर लिए जाने वाले शुल्क को माफ करने से भी आयातक इसे उठाने में जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं।

नागर विमानन मंत्रालय ने पिछले महीने माल का उठान होने में देरी पर लगने वाले शुल्क को 50 फीसदी माफ करने का आदेश दिया था ताकि आवश्सयक वस्तुओं की आपूर्ति सुगम हो सके। हालांकि सीमा शुल्क विभाग का मानना है कि इससे न केवल आयातक और ब्रोकरों द्वारा अपने खेप उठाने को हतोत्साहित हुए हैं बल्कि बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर कार्गो की भीड़ भी बढ़ गई है।

सूत्रों ने कहा कि दिल्ली हवाई अड्डे पर करीब 3,000 टन इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सामान और वाहन उत्पाद पुर्जे पड़े हैं। दिल्ली हवाई अड्डे पर तैनात एक सीमा शुल्क अधिकारी ने कहा, 'टर्मिनलों से चिकित्सा और आवश्यक आपूर्ति को छोड़कर बाकी कार्गो का निपटान बड़ी समस्या बन गई है। ये माल इसलिए भी नहीं हटाए जा रहे हैं क्योंकि ट्रकों, ट्रॉलियों और श्रमिकों की किल्लत भी है।'

उधर, उद्योग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि देश में औद्योगिक उत्पादन घटने से बंदरगाहों पर कार्गो की आवाजाही में पिछले कुछ हफ्तों के दौरान 50 से 60 फीसदी की कमी आई है। अगर लॉकडाउन जारी रहा तो कार्गो की आवाजाही में और 10 से 15 फीसदी की कमी आ सकती है। इससे शिपिंग कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। एक निजी बंदरगाह के अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर कहा, 'बंदरगाहों पर ज्यादातर काम मैलुअल होते हैं और श्रमिकों की कमी से दिक्कत आ रही है। वेटिंग अवधि चार से पांच दिन हो गई है। कोस्टल कार्गो की आवाजाही भी प्रभावित हुई है और केवल 40 फीसदी जहाज ही चल रहे हैं।' उन्होंने कहा कि उद्योगों द्वारा उत्पादन में कटौती करने की घोषणा और मांग घटने से बंदरगाहों पर नए माल नहीं आ रहे हैं।

कोकिंग कोयला, तापीय कोयला और उर्वरक जैसे बल्क उत्पाद कोस्टल कार्गो के जरिये आते हैं। एक अधिकारी ने कहा, 'तूतीकोरिन जैसे बड़े बंदरगाह मुश्किल में हैं और जल्द ही ऊोर्स मेज्योर की घोषणा कर सकते हैं।'

लॉकडाउन ने बढ़ाई दूरसंचार फर्मों की आय

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल

- मार्च तिमाही में कंपनियों की प्रति ग्राहक औसत आय 15 फीसदी तक बढ़ी
- वित्त वर्ष 2020 की चौथी तिमाही में प्रति ग्राहक औसत आय 140 से 145 रुपये रही
- चालू वित्त वर्ष में कंपनियां करेंगी 3 से 4 अरब डॉलर का पूंजीगत निवेश, जो पिछले साल की तुलना में है आधा

कोरोनावायरस के प्रकोप और देशव्यापी बंदी की वजह से जहां अन्य उद्योगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं दूसरी ओर दूरसंचार कंपनियों की आय मार्च में खत्म होने वाली 2020 तिमाही पिछले पिछली की तुलना में 15 फीसदी बढ़ी है। असल में मार्च के दौरान डेटा की मांग बढ़ने से कंपनियों को फायदा हुआ है।

दूरसंचार उद्योग के संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने अपने सदस्यों भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो आदि से मिली जानकारी के आधार पर अनुमान लगाया है कि मार्च तिमाही में प्रति ग्राहक औसत आय 140 से 145 रुपये रही, जो दिसंबर, 2019 में खत्म हुई तिमाही में 124 रुपये थी। सीओएआई के महानिदेशक राजन मैथ्यू ने कहा, 'आय में वृद्धि मुख्य रूप से डेटा की अप्रत्याशित मांग की वजह से हुई है। लॉकडाउन के बाद विभिन्न क्षेत्र के कर्मचारियों के घर से काम करने की वजह से मार्च तिमाही में डेटा की खपत 15 से 30 फीसदी बढ़ी है। इसके बावजूद नए ग्राहकों की संख्या मार्च में महज 5 लाख बढ़ी जबकि लॉकडाउन से पहले प्रति माही औसतन 25 लाख नए ग्राहक जुड़ रहे थे।'

मैथ्यू ने कहा कि राजस्व और ज्यादा हो सकता था लेकिन दूरसंचार कंपनियों द्वारा मुफ्त में अधिक डेटा और कॉल के लिए अतिरिक्त मिनट देने की वजह से राजस्व थोड़ा कम रहा। कोविड-19 का संक्रमण शुरू होने के बाद से कंपनियों ने ग्राहकों को करीब 600 करोड़ रुपये मूल्य की सेवाएं मुफ्त में दी हैं। दूरसंचार कंपनियों का अनुमान है कि नए वित्त वर्ष में उनकी आय 10 से 12 फीसदी बढ़ सकती है क्योंकि स्कूलों द्वारा ई-क्लास शुरू करने से अगली तिमाही में भी मांग बनी रहेगी। इसके साथ ही कंपनियों को आर्थिक संकट के समय ग्राहकों की संख्या में कमी का भी अंदेशा नहीं हैं, क्योंकि मोबाइल संचार का जरूरी साधन बन गया है। कंपनियों को उम्मीद है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद नए ग्राहकों की संख्या भी पहले की तरह बढ़ने लगेगी।

दूरसंचार उद्योग की सदस्य कंपनियों का अनुमान है कि प्रति ग्राहक औसत आय 180 रुपये तक पहुंच सकती है, जो कोविड-19 से पहले के उनके 200 रुपये के अनुमान के करीब है। इससे माना जा रहा है कि शुल्क दरों में एकबार फिर इजाफा किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल शुल्क दरें बढ़ाना आसान नहीं दिख रहा है लेकिन कंपनियां प्रति ग्राहक औसत आय के लक्ष्य के करीब पहुंच सकती हैं।

कंपनियों से मिली जानकारी के आधार पर सीओएआई का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में पूंजीगत निवेश पिछले साल की तुलना करीब आधी रह सकती है।

हवाईअड्डे के टर्मिनलों पर फैसला बाद में

एजेंसियां
नई दिल्ली, 10 अप्रैल

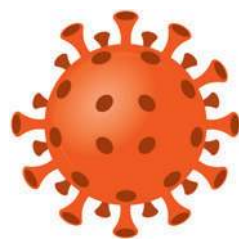

दिल्ली हवाईअड्डा का संचालन करने वाली दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनैशनल लिमिटेड (डायल) विमानन कंपनियों के साथ मिलकर लॉकडाउन के बाद की स्थिति में विमान यातायात मांग का आकलन कर रहा है। डायल इस बात पर भी गौर करेगी कि टर्मिनलों की मजबूती के लिए कदम उठाने की जरूरत है या नहीं। चार दिन पहले सिंगापुर सरकार ने घोषणा की थी कि चांगी हवाईअड्डा अपने दो टर्मिनलों को अगले महीने से डेढ़ साल तक के लिए बंद करेगा, क्योंकि कोरोनावायरस महामारी के चलते विमान यात्रियों की संख्या बहुत घट गई है।

दिल्ली हवाईअड्डे पर तीन टर्मिनल हैं, जबकि सिंगापुर के चांगी हवाईअड्डे पर चार टर्मिनल हैं। जीएमआर ग्रुप की अगुआई वाली डायल ने एक बयान में स्पष्ट किया कि उसकी वर्तमान विस्तार कार्य को टालने की तत्काल कोई योजना नहीं है। डायल ने एक बयान में कहा,'परिचालन पर निलंबन हट जाता है तब डायल विमानन कंपनियों के साथ घरेलू मांग का आकलन करेगा। टर्मिनलों के परिचालन की मजबूती की संभावना समेत विभिन्न विकल्पों पर विमान की जरूरतों एवं सरकारी अधिसूचनाओं के आधार पर गौर किया जा रहा है।'

डायल ने कहा कि लॉकडाउन के चलते वाणिज्यिक परिचालन पर रोक के दौरान दिल्ली हवाईअड्डा रोजाना 25-30 परिचालनों मुख्य तौर पर मालवाहक एवं निकालने संबंधी अभियानों को संभालता है। फिलहाल, किसी भी विस्तार कार्य को टालने की तत्काल कोई योजना नहीं है। लॉकडाउन के बीच मालवाहक उड़ानों, मेडिकल बचाव उड़ानों एवं विशेष उड़ानों के परिचालन की अनुमति दी गई हैं।

मंडी में फल-सब्जी की आवक घटी

लॉकडाउन के कारण तमाम फल एवं सब्जी मंडियां बंद हैं या उनमें लगी है कई तरह की पाबंदी

राजेश भयानी
मुंबई, 10 अप्रैल

देश में जिंसों की आवक

आवक (टन में)	1 मार्च-23 मार्च	24 मार्च-10 अप्रैल	कमी (प्रतिशत में)
सेब	44,157	14,950	66.1
केला	65,004	31,977	50.8
अंगूर	30,188	14,871	50.7
प्याज	441,103	129,058	70.7
आलू	597,573	236,598	60.4
भिंडी	19,220	11,667	39.3
गेहूं	949,913	80,022	91.6
अरहर	63,566	16,354	74.3
चावल	279,992	118,822	57.6

स्रोतः एगमार्कनेट डॉट गॉव डॉट इन
संकलनः बीएस रिसर्च ब्यूरो

लॉकडाउन के कारण देश के सब्जी और फल किसान बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। थोक मडियों में सब्जी और फलों की आवक में भारी गिरावट इसका प्रमाण है। लॉकडाउन के कारण देश भर में सब्जी और फल मंडियां बंद हैं या फिर उनमें कई तरह की पाबंदियां लगी हुई हैं।

मुंबई के करीब वाशी सब्जी एपीएमसी बाजार ने कोविड-19 के संक्रमण की आशंका को देखते हुए मंडी बंद करने का फैसला किया है। पुणे का गुलटेकड़ी थोक बाजार भी कल बंद हो गया जिससे आसपास के सब्जी किसान बुरी तरह प्रभावित हुए।

अगर महानगरों में कोविड-19 का संक्रमण बढ़ता है तो सब्जियों और अनाज जैसे जरूरी चीजों की भारी किल्लत हो सकती है। आगरा मंडी में अभी से आलू की आवक 30 फीसदी गिरकर 1,400 टन रोजाना ही रह गई है। नासिक के करीब लासलगांव में इस समय प्याज की आवक चरम पर होती थी, लकिन यह मंडी कई दिनों से बंद है। पहले यह साल खत्म होने के कारण बंद थी और उसके बाद संक्रमण फैलने की आशंका में खुली ही नहीं। पूरे देश में विभिन्न जिंसों की आवक में पिछले तीन हफ्तों में भारी गिरावट आई है। दिल्ली की आजादपुर मंडी और देश की तमाम बड़ी सब्जी-फल मंडियों का यही हाल है। मंडियां या तो बंद हैं या सीमित मात्रा में माल लाने की इजाजत है। इससे उकताकर देश में कई जगह किसानों ने सब्जियां और दूध सड़कों पर ही फेंक दिए क्योंकि या तो वे माल मंडियों तक नहीं पहुंचा पाए या उनके पास से माल उठाया नहीं जा सका। उत्तर प्रदेश और कई उत्तरी राज्यों में खेतों से सब्जी उखाड़ने की भी घटनाएं हुई हैं।

क्रेडिट सुइस रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक भरपूर पैदावार के बावजूद बाजार में पिछले साल के मुकाबले 50 से 95 फीसदी तक कम आवक है। अगर लॉकडाउन अवधि की बात की जाए तो इस दौरान सभी तरह की सब्जियों, फलों और अनाज की आवक में भारी गिरावट आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रबी का मौसम अपने शबाब पर है, इसलिए बाजार में गेहूं, चना जैसे दलहन और आम जैसे फलों की आवक में तेजी आनी चाहिए थी। लेकिन ट्रकों की कमी और माल लादने-उतारने के लिए मजदूरों की किल्लत के कारण आवक घटी है।

अनाज और दलहन किसानों की स्थिति सब्जी और फल किसानों की तरह दयनीय नहीं है मगर अनाज मंडियां बंद हैं। ■ शेष पृष्ठ 8

संक्षेप में

ज़ी ने सहायक कंपनी में किए 522 करोड़ रु. निवेश

मीडिया दिग्गज ज़ी एंटरटेनमेंट ने तकनीकी सहायक मार्गो नेटवर्क्स में 522 करोड़ रुपये निवेश किए हैं। मार्गो शुगरबॉक्स ब्रांड नाम से स्ट्रीमिंग और विज्ञापन सेवा देती है। मार्गो में ज़ी की हिस्सेदारी 80 फीसदी है और अतिरिक्त निवेश का इस्तेमाल परिचालन और वित्तीय समर्थन में किया जाएगा। ज़ी एंटरटेनमेंट के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी पुनीत गोयनका ने कहा, शुगरबॉक्स में हमारा निवेश पूरे डिजिटल कारोबार को मजबूत बनाता है। अद्भुत तकनीक हमें देश भर के ग्राहकों को कंटेंट मुहैया कराने में सक्षम बनाएगा और वहां कनेक्टिविटी का अवरोध नहीं होगा। *बीएस*

टीसीएस का चौथी तिमाही का परिणाम 16 अप्रैल को

सॉफ्टवेयर सेवा कंपनी टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज (टीसीएस) अपना 2019-20 की चौथी तिमाही का परिणाम 16 अप्रैल को घोषित करेगी। स्टॉक एक्सचेंज को भेजी सूचना में कंपनी ने कह है कि उसके निदेशक मंडल की बैठक गुरुवार, 16 अप्रैल को होगी, जिसमें लेखा-परीक्षा वाले वित्तीय परिणाम को मंजूरी दी जाएगी। निदेशक मंडल इस बैठक में वित्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश की घोषणा भी कर सकता है। प्रतिस्पर्धी कंपनी विप्रो 15 अप्रैल को 2019-20 की चौथी तिमाही और वित्त वर्ष के लिए परिणाम की घोषणा करेगी। *भाषा*

उद्योग का जोर नकदी बचाने पर

बड़े कारोबारी समूह, ऊंची रेटिंग वाली कंपनियां भी ऋण पर मोहलत का लाभ उठाएंगे

अमृता पिल्लई
मुंबई, 10 अप्रैल

- ऐसी कंपनी ने भी इस मोहलत का फायदा उठाने का निर्णय लिया है जिसके बहीखाते में 2,100 करोड़ रुपये की नकदी है
- कुछ ऐसी कंपनियां भी इस विकल्प को स्वीकार कर रही हैं जिनकी रेटिंग 'एएए' है
- रेटिंग अधिकारियों का कहना है कि अनिश्चितता के कारण कंपनियां उधारी की ऊंची लागत को स्वीकार कर रही हैं

भारत की ऊंची रेटिंग वाली कंपनियां ऋण अदायगी के मोर्च पर आरबीआई द्वारा दी गई मोहलत का फायदा उठा रही हैं जिससे पता चलता है कि वे लंबी अवधि के लिए तैयारी कर रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कंपनियां इस समय नकदी बचाकर रखने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं क्योंकि कोरोनावायरस (कोविड-19) वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए किए गए 21 दिवसीय देशव्यापी लॉकडाउन के प्रभाव एवं अवधि को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।

मोहलत का लाभ उठाने वाली कंपनियों की सूची में प्रतिष्ठित समूह की कंपनियां और अपेक्षाकृत बेहतर वित्तीय स्थायित्व वाली कंपनियां भी शामिल हैं। उदाहरण के लिए, टाटा पावर ने इस मोहलत को स्वीकार करने की योजना बनाई है। टाटा पावर ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा, 'हम ब्याज एवं ऋण के पुनर्भुगतान के लिए बैंकों द्वारा दी गई तीन महीने की मोहलत का फायदा उठाएंगे।'

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ऋण देने वाले संस्थानों को 1 मार्च से 31 मई के बीच ऋण के किस्तों के भुगतान पर उधारकर्ताओं को तीन महीने की मोहलत देने की अनुमति दी है। ऐसा कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण हुए वित्तीय व्यवधान से निपटने के लिए उधारकर्ताओं की मदद के लिए किया गया है।

केयर रेटिंग्स के सहायक निदेशक, समूह प्रमुख (इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐंड प्रोजेक्ट फाइनैंस) रत्नम राजू ने कहा, 'हम देख रहे हैं कि ऊंची रेटिंग वाली कंपनियां भी नकदी बचाकर रखने के लिए मोहलत का फायदा उठाने के लिए सामने आ रही हैं। इनमें से कुछ कंपनियां तो बड़े कारोबारी समूह की इकाइयां हैं।'

विभिन्न कंपनियों से सूचनाएं हासिल करने वाले रेटिंग उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कुछ ऐसी कंपनियां भी इस विकल्प को स्वीकार कर रही हैं जिनकी रेटिंग 'एएए' है। इन कंपनियों को समयबद्ध तरीके से ऋण अदायगी संबंधी क्षमता के लिए ऊंची रेटिंग मिली हुई है।

जहां तक जेएसडब्ल्यू समूह का सवाल है तो उद्योग सूत्रों के अनुसार इस समूह की कुछ कंपनियों ने मोहलत को स्वीकार किया है लेकिन कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह पूरी तरह सच नहीं है क्योंकि पूरे समूह ने सभी बैंक ऋण पर इसका फायदा नहीं उठाया है।

हालांकि कुछ अपवाद भी हैं। लार्सन ऐंड टुब्रो के एक शीर्ष अधिकारी के अनुसार, कंपनी इस मोहलत का फायदा नहीं उठाएगी। आदित्य बिड़ला समूह के प्रवक्ता ने तत्काल इस मुद्दे पर टिप्पणी नहीं की कि उनके समूह की कंपनियां ऋण पुनर्भुगतान में दी गई मोहलत का फायदा उठएंगी अथवा नहीं।

अदाणी समूह को इस बाबत जानकारी के लिए भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उसकी परिवहन इकाई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'कंपनी ने अपनी सड़क एवं जल परियोजनाओं के लिए बैंकों से फिलहाल कोई ऋण नहीं लिया है।'

रेटिंग अधिकारियों का कहना है कि अनिश्चितता के कारण कंपनियां उधारी की ऊंची लागत को स्वीकार कर रही हैं। एक अधिकारी ने कहा कि एक ऐसी कंपनी भी इस मोहलत का फायदा उठाने का निर्णय लिया है जिसके बहीखाते पर 2,100 करोड़ रुपये की नकदी उपलब्ध है।

आधी क्षमता पर काम करेगी इंडिगो

अरिदम मजूमदार
नई दिल्ली, 10 अप्रैल

जब सेवा बहाल होगी तो देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो 50 फीसदी क्षमता पर परिचालन करेगी। विमानन कंपनी उड़ान में भोजन की सेवा बंद कर देगी। कंपनी के सीईओ रणजय दत्ता ने शुक्रवार को कर्मचारियों को यह जानकारी दी। इसके अलावा विमानों में बार-बार और बेहतर साफ-सफाई करेगी। जब विमानन कंपनी फिर से परिचालन शुरू करेगी तो क्रू व यात्रियों की सुरक्षा के लिए इन कदमों के अलावा कई और बदलाव लागू किए जाएंगे।

विमानों की गहराई से सफाई करेगी, एयरोपोर्ट की बसें आधी भरी होंगी

कोरोनावायरस महामारी पर लगाम कसने के लिए भारत में 21 दिन का लॉकडाउन लागू है। सरकार चरणबद्ध तरीके से दोबारा परिचालन शुरू करने की योजना बना रही है, जिसका मतलब यह हुआ कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद कुछ ही मार्गों पर सेवा शुरू होगी।

दत्ता ने ईमेल में कहा है, सुरक्षा को लेकर हम हमेशा ही सतर्क रहे हैं। हमें अब स्वास्थ्य के प्रति भी सतर्क रहना होगा। हम लगातार और बार-बार विमानों की अच्छे से साफ-सफाई करेंगे और थोड़े समय के लिए उड़ान में भोजन की सेवा बंद कर देंगे और अपने कोच का परिचालन अधिकतम 50 फीसदी लोड पर करेंगे। हम जल्द ही नया प्रोटोकॉल सामने रखेंगे।

विमानन नियामक डीजीसीए भी प्रोटोकॉल तैयार कर रहा है ताकि जब उड़ान बहाल हो तो विमान और एयरपोर्ट जैसी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित हो। विमानन कंपनियों को तब तक इस प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जब तक कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यह घोषित न कर दे कि कोरोनावायरस का खात्मा हो गया है। जिसके बारे में एजेंसी का मानना है कि अभी इसमें वक्त लगेगा। इस प्रोटोकॉल में विमानन कंपनियों को बीच वाली सीट और आखिरी तीन पंक्ति खाली रखने को कहा जाएगा। साथ ही उड़ान के दौरान खाने-पीने की चीजों की बिक्री और ड्यूटी फ्री सामान की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। इसके अलावा एक समय में भीड़भाड़ को रोकने के लिए सिर्फ तीन पंक्ति के यात्रियों को विमान में चढ़ने दिया जाएगा।

ईमेल में कहा गया है, ऐसी परिस्थितियों में कंपनियां लाभ के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहती बल्कि नकदी के कारण। ऐसे में हमारा ध्यान नकदी प्रवाह पर होगा। हम सभी फिक्स्ड लागत का आकलन कर रहे हैं और उन्हें घटाने के तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं। 50 फीसदी क्षमता बनाए रखने का मतलब यह होगा कि इंडिगो 186 सीटों वाली 93 एयरबस ए 320 विमानों का ही परिचालन कर पाएगी। उम्मीद की जा रही है कि अन्य विमानन कंपनियां भी ऐसा ही रुख अपनाएंगी। दत्ता ने कहा, हम सभी हितधारकों ग्राहक, कर्मचारी और निवेशक को ध्यान में रखकर फैसला ले रहे हैं।

अधिकारी ने कहा, सोशल डिस्टेंसिंग के सख्त नियम से इस क्षेत्र की रिकवरी में काफी वक्त लग जाएगा, जो कोरोनावायरस के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। अधिकारी ने कहा, जब विमान 90 फीसदी भरे होते हैं तब भी विमानन कंपनियां कमाई नहीं करती। एक विमानन अधिकारी ने कहा, अगर मैं 180 सीट वाला विमान दिल्ली-मुंबई के बीच चला रहा हूं और न्यूनतम शुल्क 5,000 रुपये हो तो 80 सीट में कमी का मतलब यह है कि किराया कम से कम 10,000 रुपये होना चाहिए। ऐसे समय में जो महंगा किराया चुकाएंगे, वही उड़ान भर पाएंगे। उनकी कंपनी पिछले चार दिन में 15 टिकट ही बेच पाई है।

कैडिला हेल्थकेयर के शेयर में उछाल

उज्ज्वल जौहरी
मुंबई, 10 अप्रैल

पिछले करीब एक साल से तेजी की उम्मीद देख रहे कैडिला हेल्थकेयर के शेयर में पिछले दो दिनों में 28 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज हुई है। बुधवार को एक दिन के कारोबार में 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर 366.55 रुपये को छूने के बाद यह 350 रुपये पर बंद हुआ। हाल ही में अमेरिका को मलेरिया रोधी दवा हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन (एचसीक्यू) की आपूर्ति करने से लाभ होने के संकेतों के चलते शेयर बाजार की धारणा में बदलाव आया है।

कंपनी के प्रवक्ता ने संकेत दिया कि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एचसीक्यू के मासिक उत्पादन को पहले ही 3 मीट्रिक टन से 20-30 मीट्रिक टन (10 करोड़ से अधिक टैबलेट) तक बढ़ाया गया है।

अमेरिकी दृष्टिकोण में सुधार के अलावा घरेलू बाजार में भी कंपनी के लिए संभावनाएं मजबूत हुई हैं। घरेलू बाजार लगभग 10 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है और कैडिला को अपने राजस्व का लगभग 40 प्रतिशत भारत से प्राप्त होता है। कंपनी ने कुछ आंतरिक परिवर्तन किए थे और अब मजबूती के साथ बिक्री को गति दी गई है। निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के विश्लेषकों का कहना है कि मार्च 2020 की तिमाही में कैडिला हेल्थकेयर के प्रदर्शन को घरेलू व्यापार में वृद्धि से जोड़कर देखा जाना चाहिए। भले ही वेलनेस बिजनेस की ग्रोथ सामान्य से कम हो, लेकिन इसकी संभावनाएं काफी मजबूत हैं।

सीआईएसएफ का उड़ान प्रस्ताव

अनीश फडणीस
मुंबई, 10 अप्रैल

सीआईएसएफ ने प्रस्थान से दो घंटे पहले चेक-इन काउंटर को बंद करने का सुझाव दिया

भारतीय हवाई अड्डों की सुरक्षा में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने हवाई परिचालन शुरू करने और हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ से बचने एवं सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए उड़ान के प्रस्थान से दो घंटे पहले चेक-इन काउंटर को बंद करने की सिफारिश की है। ये सुझाव सीआईएसएफ द्वारा नागर विमानन मंत्रालय को सौंपी गई कारोबार निरंतरता योजना का हिस्सा हैं। देशव्यापी लॉकडाउन के कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को 14 अप्रैल तक निलंबित कर दिया गया है।

नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा था कि यदि सरकार को भरोसा हो जाएगा कि कोरोनावायरस का प्रसार नियंत्रित है और इससे नागरिकों को कोई खतरा नहीं है तो सभी पाबंदियों को हटा दिया जाएगा। हालांकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय सभी विमानन कंपनियों के लिए उड़ान के दौरान विमान के सभी मध्य सीटों को खाली रखना अनिवार्य करने जा रहा है। इस बीच सीआईएसएफ ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अपनी सिफारिश सौंपी है।

सीआईएसएफ के विशेष महानिदेशक (हवाई अड्डा क्षेत्र) एमए गणपति ने कहा, 'विमानन कंपनियों को किसी भी समय बड़ी संख्या में यात्रियों के एकत्रित होने से बचने के लिए उड़ान के समय में काफी अंतराल देना चाहिए। इससे सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और हवाई अड्डे पर विभिन्न प्रक्रियाओं को पूरा करने में आसानी होगी।' सीआईएसएफ देश भर के 63 हवाई अड्डों को सुरक्षा प्रदान करता है। सीआईएसएफ ने चेक-इन प्रक्रिया में भी बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है। उसने कहा है कि क्वारंटाइन में जाने वाले यात्रियों को खुद घोषणा करनी चाहिए ताकि उनके लिए अलग बूथ की व्यवस्था की जा सके।

आईटीसी ने उतारा सैनिटाइजर

कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण हैंड सैनिटाजर की जबरदस्त वैश्विक मांग को देखते हुए सिगरेट से लेकर होटल जैसे क्षेत्रों में कारोबार करने वाली प्रमुख कंपनी आईटीसी ने अपने सैवलॉन ब्रांड के तहत एक नया हैंड सैनिटाइजर उतारा है। इसकी 250 मिलीलीटर शीशी की कीमत 250 रुपये रखी गई है। कंपनी ने दावा किया है कि यह फॉर्मूलेशन त्वरित एवं लगातार दोनों तरह से प्रभावी है और यह वायरस के अलावा 99.99 फीसदी बैक्टीरिया एवं कवक को खत्म करने में समर्थ है। कंपनी ने इस उत्पाद को सैवलॉन हेक्सा के नाम से बाजार में उतारा है और इसका लक्षित वर्ग उपभोक्ताओं के अलावा चिकित्सा पेशेवर भी हैं। कंपनी इसे देश भर के बाजारों में उतारने की तैयारी कर रही है। *बीएस*

वाहन क्षेत्र में लंबी चलेगी मंदी

सुरजीत दास गुप्ता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल

कोविड-19 के कारण वाहन क्षेत्र नई चुनौतियों के लिए तैयार हो रहा है। दूसरी ओर, लोगों की जेब पर पड़ी मार के चलते वे नए वाहन खरीदने की योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया है और दोपहिया तथा यात्री वाहन बिक्री के बड़े हिस्से में पुरानी वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए ऑटोमोटिव ओईएम कंपनियों को अपने पूर्व स्वामित्व वाले वाहन व्यवसाय को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ओला, उबर की तरह साझा सेवाएं देने वाली कंपनियों का कारोबार आने वाले महीनों में हल्का रहेगा और लोग अपने निजी वाहनों से सफर करने को तरजीह देंगे। हालांकि इससे यात्री कार क्षेत्र में मजबूती देखने को मिल सकती है। कंसल्टेंसी फर्म पीडब्ल्यूसी ने सायम के लिए कोरोनावायरस के प्रभाव का आकलन करने के लिए तैयार की गई रिपोर्ट में ये बातें कही हैं। पीडब्ल्यूसी का कहना है कि एक यथार्थवादी परिदृश्य में ऑटो उद्योग को वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में जाकर बहुत धीमी सुधार दिखाई देगी और अगर निराशावादी परिप्रेक्ष्य देखें तो वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में कहीं जाकर सुधार देखने को मिलेगी। दोनों ही मामलों में पीडब्ल्यूसी ने वेतन कटौती, अस्थायी नौकरी के नुकसान और खराब वित्तीय स्थिति की भविष्यवाणी की है। पीडब्ल्यूसी ने चेतावनी दी है कि वित्त वर्ष 2021 में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 18 प्रतिशत, यात्री कारों की बिक्री में 12 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री में 21 प्रतिशत की कमी आएगी।

टाइटन की होगी बड़ी चुनौती

राम प्रसाद साहू
मुंबई, 10 अप्रैल

मार्च महीने में टाइटन की बिक्री पर लॉकडाउन का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और आपूर्ति में बाधा एवं खुदरा स्टोरों के बंद होने से चौथी तिमाही में कंपनी के आभूषण क्षेत्र में 5 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी की कुल बिक्री में इस क्षेत्र की 80 फीसदी हिस्सेदारी है। हालांकि जनवरी तथा फरवरी महीने में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही थी जिससे राजस्व में कुल 16.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

टाइटन ने संकेत दिया कि मार्च में परिचालन ठप्प हो जाने के कारण, चौथी तिमाही तथा वित्त वर्ष 2019-20 की कुल राजस्व वृद्धि बहुत अधिक प्रभावित होगी। ब्रोकरेजों का मानना है कि इसका प्रभाव और अधिक गंभीर हो सकता है। आमतौर पर जून तिमाही में कुल राजस्व की लगभग 24 प्रतिशत कमाई हो जाती है जिसके चलते यह काफी महत्त्वपूर्ण तिमाही है। इसके ठीक बाद शादी की सीजन शुरू होता है जो बिक्री बढ़ाने का अहम कारक है। इस महामारी से पहले तक हीरे जड़ित आभूषणों की काफी अच्छी मांग थी लेकिन शादियों के रद्द हो जाने तथा खुदरा स्टोरों के विस्तार में देरी के चलते बिक्री में गिरावट से वित्त वर्ष 2021 के राजस्व पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इस तिमाही में कंपनी ने 1,51,000 वर्ग फुट क्षेत्र में 40 नए तनिष्क स्टोर खोले हैं। हालांकि कुछ ब्रोकरेज को उम्मीद है कि जून तिमाही में आभूषणों की बिक्री में 40 फीसदी की गिरावट आएगी लेकिन यह बहुत हद तक लॉकडाउन को हटाने पर निर्भर करेगा।

मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज का कहना है कि टाइटन के अधिकांश स्टोर मॉल में थे और अब मॉल के बंद होने के चलते कंपनी की बिक्री बहुत अधिक प्रभावित होगी। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी मॉल में लोगों की आवाजाही सीमित ही रहेगी क्योंकि लोग सोशल डिस्टेंटिंग बनाए रखना चाहेंगे। इस समय कंपनी कीमतों को कम करने के साथ ही आपूर्ति शृंखला को बेहतर बनाने हुए पर्याप्त तरलता बनाए रखने का प्रयास कर रही है।

कॉरपोरेट चूक पर रुख होगा साफ

श्रीमी चौधरी
नई दिल्ली, 10 अप्रैल

महामारी पड़ी भारी

- म्युचुअल फंडों ने लॉकडाउन की वजह से एनबीएफसी चूक की आशंका के बीच सेबी से संपर्क किया है
- मार्च में शेयर बाजार में गिरावट के बीच डेट योजनाओं में भी भारी बिकवाली दबाव देखा गया था
- कई डेट फंड श्रेणियों में ऋण जोखिम की मात्रा पर प्रतिबंध नहीं है
- चूक के प्रबंधन के संदर्भ में सेबी के स्पष्टीकरण से फंड हाउसों को चूक के बाद खुले बाजार में बिक्री के बगैर प्रतिभूतियों को बनाए रखने की अनुमति मिलेगी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) कॉरपोरेट चूक के प्रबंधन को लेकर म्युचुअल फंडों (एमएफ) के लिए जल्द स्थिति स्पष्ट करेगा। म्युचुअल फंडों ने नियामक से संपर्क किया है और कई मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। यह पहल बढ़ते रिडम्पशन दबाव, बॉन्ड बाजार में गतिविधि के अभाव और लॉकडाउन की वजह से कंपनियों द्वारा बकाया के गैर-भुगतान की आशंकाओं के बीच सामने आई है। कुछ कंपनियों ने यह स्पष्ट किया है कि उन्हें रिडम्पशन दबाव को देखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली उधारी पर ध्यान देने की जरूरत होगी।

एक नियामकीय अधिकारी ने कहा, 'हम म्युचुअल फंडों के समक्ष पैदा हुईं चुनौतियों की समीक्षा कर रहे हैं और संभावित समाधान की दिशा में काम कर रहे हैं। नियामक ने इस तरह की चुनौतियां दूर करने के लिए कई नियम पेश किए हैं और जरूरत पड़ने पर लगातार दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।'

एमएफ उद्योग को भुगतान में विलंब और कंपनियों (खासकर कोविड-19 महामारी के बीच एनबीएफसी) द्वारा चूक की वजह से भी दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

मौजूदा समय में, कई डेट फंड श्रेणियों में ऋण जोखिम की मात्रा पर प्रतिबंध नहीं है। अधिकारी ने कहा कि चूक के प्रबंधन के संदर्भ में सेबी के स्पष्टीकरण से फंड हाउसों को चूक के बाद खुले बाजार में बिक्री के बगैर प्रतिभूतियों को बनाए रखने की अनुमति मिलेगी।

मार्च में, कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से बाजारों में भारी बिकवाली के बाद डेट योजनाओं में रिडम्पशन दबाव दर्ज किया गया था। इस उद्योग ने मार्च महीने में डेट योजनाओं से 1.94 लाख करोड़ रुपये की निकासी दर्ज की। पिछले साल सेबी ने मौजूदा निवेशकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डेट म्युचुअल फंडों को फंसी परिसंपत्तियों को अन्य लिक्विड निवेश

> एक विशेषज्ञ ने कहा, म्युचुअल फंड बैंक नहीं हैं, इसलिए किसी तरह की मोहलत इस उद्योग के लिए उपयोगी साबित नहीं होगी

से अलग करने की अनुमति दी थी।

वैल्यू रिसर्च के संस्थापक धीरेंद्र कुमार ने कहा, 'म्युचुअल फंड बैंक नहीं हैं, इसलिए किसी तरह की मोहलत इस उद्योग के लिए उपयोगी साबित नहीं होगी। मौजूदा परिवेश में भारी रिडम्पशन दबाव देखा जाता है क्योंकि निवेशकों को निवेश से बाहर निकलने के लिए तीन महीने तक इंतजार करने को नहीं कहा जा सकेगा। इसलिए नियम स्पष्ट है कि यदि गैर-तरलता की स्थिति अचानक आती है तो साइड पॉकेटिंग प्रावधान को खराब प्रतिभूतियों को अच्छे निवेश से अलग करने की अनुमति के लिए समर्थ बनाया जा सकेगा।'

एम्फी के एक सदस्य ने कहा, 'कानून स्पष्ट है कि फंड हाउसों को चूक पर सुरक्षा और सख्ती बरतने के लिए बाध्य होना होगा। यदि जरूरत पड़ी तो वे पोर्टफोलियो प्रावधान के विभाजन पर ध्यान दे सकते हैं।' बाजार नियामक के लिए उपयुक्त समय आ गया है और उसने निवेशकों को क्रेडिट के साथ साथ लिक्विड जोखिम से बचाने के लिए फिर से डेट फंडों (लिक्विड फंड शामिल) के लिए नियम सख्त किए हैं। ये बदलाव खासकर आईएलऐंडएफएस में चूक के बाद सामने आए हैं। चूक से जुड़े ऋणदाता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए उधारी को लेकर चौकस हैं जिससे ऋण पर दबाव की समस्या पैदा हो गई है।

एनबीएफसी पर दोहरी मार, नकदी दबाव व ग्राहकों को मिली मोहलत

एनबीएफसी को जून 2020 तक 1.75 लाख करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान करना है

अभिजित लेले
मुंबई, 10 अप्रैल

- अगर एनबीएफसी को देनदारों से मिलने वाली रकम में तेजी नहीं आती है तो उन्हें नकदी के दबाव का सामना करना पड़ेगा
- एनबीएफसी दोहरी मार का सामना कर रही है क्योंकि लेनदार बैंकों की तरफ से मोहलत न मिलने के बावजूद अपने ग्राहकों को मोहलत की पेशकश कर रही हैं

भारतीय गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को जून 2020 तक 1.75 लाख करोड़ रुपये के कर्ज का भुगतान करना है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक, अगर उनके देनदारों से मिलने वाली रकम में तब तक तेजी नहीं आती है तो उन्हें नकदी के दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

आईएलऐंडएफएस के घटनाक्रम के बाद कई वित्तीय कंपनियां पहले ही नकदी की चुनौतियों का सामना कर रही है। अब कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन ने वित्तीय कंपनियों का फील्ड ऑपरेशन प्रभावित किया है, लिहाजा संग्रह पर भी असर पड़ा है।

क्रिसिल ने एक बयान में कहा, हमारी रेटिंग वाली एनबीएफसी के लिए नकदी का कवर तेजी से घटेगा अगर वे अपनी बैंक उधारी पर मोहलत पाने में कामयाब नहीं होती। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 नियामकीय पैकेज के तहत कर्ज के भुगतान पर तीन महीने की मोहलत का ऐलान किया है। यह मोहलत उन देनदारों के लिए है जो अस्थायी तौर पर नकदी का दबाव झेल रहे हैं।

एनबीएफसी दोहरी मार का सामना कर रही है क्योंकि लेनदार बैंकों की तरफ से मोहलत न मिलने के बावजूद अपने ग्राहकों को मोहलत की पेशकश कर रही हैं। यह कई एनबीएफसी के नकदी प्रोफाइल पर खासा असर डालेगा।

क्रिसिल ने कहा, नई रकम जुटाना मुश्किल होगा क्योंकि बैंकों की तरह एनबीएफसी की पहुंच नकदी के व्यवस्थित स्रोत तक नहीं है और वह थोक फंडिंग पर ज्यादा निर्भर करती है।

आरबीआई ने अपने लक्षित एलटीआरओ के तहत एक लाख करोड़ रुपये उपलब्ध कराया है। हालांकि उसका आधा ही प्राथमिक इश्यू के लिए है। साथ ही फंडों के लिए संभावित छीना-झपटी होगी जब कॉरपोरेट और सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय कंपनियां इस जरिये में दिलचस्पी दिखाएंगी। इसके परिणामस्वरूप उच्च रेटिंग वाली एनबीएफसी को फायदा हो सकता है।

उच्च रेटिंग वाली एनबीएफसी लिए बड़ा निवेशक आधार म्युचुअल फंड भी निवेश निकासी का सामना कर रही है, इसलिए वह पुनर्वित्त के लिए शायद ही एक स्रोत बना रह पाएगा।

साथ ही सिक्योरिटाइजेशन पर भरोसा करने वाले कई एनबीएफसी को भी निकट भविष्य में शायद ही बहुत ज्यादा लेनदेन देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी मोहलत मिली हुई है।

क्रिसिल ने कहा कि बड़ी और बेहतर रेटिंग वाली वित्तीय फर्में अभी भी स्थिति के प्रबंधन में सक्षम है। छोटी या कम रेटिंग वाली एनबीएफसी के लिए वास्तव में मुश्किल होगी, जो बैंकों की फंडिंग पर ज्यादा निर्भर है।

डीएचएफएल प्रवर्तकों के 5 लग्जरी वाहन जब्त

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 10 अप्रैल

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने येस बैंक-राणा कपूर मामले में शुक्रवार को दीवान हाउसिंग फाइनैंस (डीएचएफएल) के प्रवर्तकों के खिलाफ धन शोधन जांच के सिलसिले में उनसे जुड़े पांच लग्जरी वाहनों को जब्त कर लिया।

इन लग्जरी कारों का इस्तेमाल कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरे देश में की गई तालाबंदी के बीच महाराष्ट्र में महाबलेश्वर स्थित उनके फार्म हाउस तक जाने के लिए किया गया। वधावन भाई दो रेंज रोवर और तीन टोयोटा फॉर्च्यूनर कारों में यात्रा कर रहे थे।

ईडी के जब्ती आदेश के अनुसार, डीएचएफएल के प्रवर्तक कपिल वधावन एवं धीरज वधावन इन लग्जरी वाहनों के मालिक हैं। ऑर्डर में कहा गया, 'जांच में पता चला है कि ये वाहन धनशोधन रोकथाम कानून के प्रावधानों के अनुसार अपराध श्रेणी में आते हैं।' उपरोक्त आदेश अमल करने के लिए सतारा पुलिस अधीक्षक को भेजा गया, क्योंकि दोनों वधावन भाइयों को कोविड-19 के तहत सतारा प्रशासन की देखरेख में क्वारंटीन किया गया था।

महामारी के चलते सभी बॉर्डर सील होने के बाद भी वधावन भाई परिवार के 21 सदस्यों के साथ वहां से निकलने में कामयाब रहे। येस बैंक मामले में केंद्रीय एजेंसियां वधावन भाइयों का पता लगाने में अक्षम साबित हुई हैं।

सूत्रों का कहना है कि लॉकडाउन की घोषणा से पहले तक वधावन महाराष्ट्र के खंडाला के बाहरी इलाके में एक वृद्धाश्रम में रह रहे थे। इसके बाद, उन्होंने ईडी तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के हालिया मामलों में जांच से बचने के लिए अपना स्थान बदल दिया था। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने एक किराये का घर लिया था।

17 मार्च को सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा उनके खिलाफ एक गैर-जमानती वारंट जारी किया गया था। गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद भी वे सीबीआई या अदालत के सामने पेश नहीं हुए।

गुरुवार को, केंद्रीय एजेंसी को वधावन के स्थान के बारे में एक सूचना मिली थी। इसके बाद, सीबीआई सतारा पुलिस के पास पहुंची और उन्हें अदालत से अनापत्ति मिलने तक कहीं भी जाने से रोकने के लिए कहा। वधावन कम से कम तीन मामलों में केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर रहा है, जिसमें पीएमसी बैंक धोखाधड़ी मामला, गैंगस्टर इकबाल मेमन के साथ संपत्ति और येस बैंक-राणा कपूर वाला मामला शामिल है।

बीएस बातचीत

भारत में लंबे समय तक लॉकडाउन सहने की क्षमता

टाटा स्टील ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के मद्देनजर अपनी इकाइयों में हो रहे उत्पादन में कटौती की है। हालांकि, टाटा स्टील के मुख्य कार्याधिकारी एवं प्रबंध निदेशक **टी वी नरेंद्रन** ने **ईशिता आयान दत्त** को बताया कि यूरोप में बिक्री सामान्य स्तर के 70 प्रतिशत पर है क्योंकि वहां लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं है। पेश है मुख्य अंश:

क्या यह लॉकडाउन पर गंभीरता से ध्यान केंद्रित करने का समय है?
महामारी को रोकने के लिए की जा रही कार्रवाइयों से समझौता किए बिना कुछ ढील दी जा सकती है। भारत बहुत बड़ा एवं जटिल संरचना वाला देश है और यहां आर्थिक गतिविधियों को अपूरणीय क्षति पहुंचाए बिना लंबे समय तक लॉकडाउन चलाया जा सकता है। इसलिए, अगर हम लोगों के स्वास्थ्य तथा जीवन से समझौता किए बिना बहुत ही चयनात्मक स्तर पर ढील दे सकते हैं।

क्या लॉकडाउन हटने के बाद आप मांग में तेजी की उम्मीद कर रहे हैं?
मुझे नहीं लगता कि कुछ समय बाद लॉकडाउन को पूरी तरह से हटा लिया जाएगा, क्योंकि महामारी को रोकने की लड़ाई अभी भी जारी है। आगे के हालात पिछले तीन हफ्तों के मुकाबले बेहतर हो सकते हैं। लेकिन स्थिति के सामान्य होने में छह महीने से लेकर एक साल तक का समय लगेगा। यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि हम महामारी का सामना किस तरह से करते हैं।

एस्मा के अंतर्गत आने के बाद भी टाटा स्टील ने परिचालन कम कर दिया, क्या यह मांग या लॉकडाउन से संबंधित है?
आपूर्ति शृंखला के प्रबंधन के मामले में पहला एक सप्ताह सबसे चुनौतीपूर्ण था। जमशेदपुर, अंगुल और कलिंगनगर में स्थित मुख्य स्टील प्लांट इकाइयों को संचालित करने की अनुमति थी। लेकिन इस्पात संयंत्र पूरी तरह से अलग होकर काम नहीं कर सकते, उन्हें चलाने के लिए कई अहम उपभोग सामग्रियों की आवश्यकता होती है। इसलिए, पहले एक सप्ताह में हम आवश्यक उपभोग योग्य वस्तुएं बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और हम 80-90 प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर रहे थे। इसके बाद हमने नकदी तथा इन्वेंट्री स्तरों का अनुकूलन करते हुए पुनर्गणना की। अधिक कच्चे माल को खरीदने में निवेश करने के बजाय कच्चे माल के अधिमूल्य पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसलिए, अभी भी पिछले 10 दिनों से हम अपने मुख्य स्थलों पर 50 प्रतिशत क्षमता के स्तर पर काम कर रहे हैं।

समूह पहले से ही विस्तार की योजना पर काम कर रहा है। हालिया स्थिति को देखते आगे क्या रणनीति होगी?
अभी हम निर्माण गतिविधियों को पूरा करने के लिए श्रम नहीं जुटा सकते हैं, आपूर्ति कर्ता भी उपलब्ध नहीं हैं और तकनीशियन उन जगहों से नहीं आ सकते हैं जहाँ हम उपकरण खरीद रहे हैं। इसलिए, अगले कुछ महीनों के लिए गतिविधियों पर विराम होगा। लेकिन चीजें कैसे बदलती हैं, इसके आधार पर हम भविष्य में उचित कदम उठाएंगे।

टाटा स्टील-यूरोप पर महामारी का क्या प्रभाव पड़ा है?
यूरोप में हमारा अनुभव थोड़ा अलग है क्योंकि वहां कोई लॉकडाउन नहीं है। वहां थोड़ी मंदी है क्योंकि कुछ ऑटो (ग्राहक) कंपनियां बंद हैं, और कुछ हद तक बिक्री में भी गिरावट है। लेकिन पैकेजिंग तथा ऐसे कई अन्य क्षेत्र हैं, जहां स्टील का उपयोग जारी है। नतीजतन, यूरोप में समूह की बिक्री सामान्य स्तर के 70 प्रतिशत पर है और हमारा मानना है कि ईस्टर के बाद जीवन सामान्य होने लगेगा।

क्या टाटा स्टील महामारी के परिणामस्वरूप नौकरी या वेतन में कटौती पर विचार करेगा?
अभी हमारा ध्यान मौजूदा कार्यबल को बेहतर उत्पादक के तौर पर विकसित करने पर है। जो सभी हमारे साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, हम उन सभी का समर्थन करते हैं। चीजें खत्म होती हैं और हमारा ध्यान लंबी अवधि की उत्पादकता पर है। हम कोई भी कठोर निर्णय नहीं लेंगे।

क्या कंपनी की योजनाएं प्रभावित होंगी?
हम इस पर काफी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि पिछले 2-3 सप्ताह में राजस्व में गिरावट आई है। हालांकि दीर्घकालिक नजरिये से देखें तो स्थिति ठीक हो जाएगी और हम अपनी योजना के अनुसार बढ़ते चलेंगे।

अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार को क्या करने की आवश्यकता है?
उद्योगों के सामने सबसे बड़ी समस्या तरलता की है, एमएसएमई और बड़े व्यवसायों, दोनों के लिए। हम एक मुश्किल दौर से बाहर आ रहे थे और पिछला साल ज्यादा अच्छा वर्ष नहीं था, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र के लिए। इसलिए सरकार के लिए पहला कदम यह होगा कि वह न केवल बैंकों के साथ मिलकर बाजार में तरलता सुनिश्चित करे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि इसका फायदा उद्योगों तक पहुंचे।

'हालिया निचले स्तर पर फिर पहुंचेगा इक्विटी व क्रेडिट मार्केट'

जेफरीज के वैश्विक इक्विटी रणनीतिकार क्रिस वुड ने अपने साप्ताहिक नोट ग्रिड ऐंड फियर में कहा है कि अगर अप्रैल के आखिर तक कोरोनावायरस महामारी का संक्रमण खत्म नहीं होता तो इक्विटी व क्रेडिट मार्केट एक बार फिर अपने हालिया निचले स्तर तक जा सकते हैं और संभवत: उससे भी नीचे फिसल सकते हैं। वुड ने कहा, अगर संक्रमण की दर अप्रैल के आखिर तक कम नहीं होती तो शेयर बाजार और क्रेडिट बाजार अपने हालिया निचले स्तर पर दोबारा पहुंच सकते हैं और यहां तक उससे भी नीचे जा सकते हैं। उस समय तक काम पर लौटने का दबाव लोगों पर बढ़ेगा क्योंकि एक निश्चित समय में अर्थव्यवस्था और लोगों की आम जीविका पर नकारात्मक असर बीमारी से भी बड़ा हो जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों में प्रोत्साहन के कारण दुनिया भर के बाजार तेजी के चरण में पहुंच गए हैं, जो मोटे तौर पर हालिया निचले स्तर से 20 फीसदी या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी बताता है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया, फिलिपींस और इंडोनेशिया पहले ही टेक्निकल बुल मार्केट में प्रवेश कर चुके हैं और अपने निचले स्तर से 20 फीसदी से ज्यादा चढ़ चुके हैं। भारतीय बेंचमार्क एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स और निफ्टी-50 भी इस निचले स्तर ऊपर आ रहे हैं। *बीएस*

लंबी बंदी नहीं झेल सकता देश

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 10 अप्रैल

सरकार मौजूदा देशबंदी के आर्थिक नुकसान का आकलन कर रही है, वहीं भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) ने कहा है कि देश लंबे समय तक बंदी नहीं झेल सकता है। हर हालत में अधिकतम सामाजिक दूरी बनाए रखने का तर्क देते हुए फिक्की ने कहा है कि आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों में संतुलन बनाए रखने के लिए गतिशील नीतिगत कदम उठाने की जरूरत है। इसमें सबसे अहम मांग विस्थापित श्रमिकों के लिए पैकेज की मांग के साथ उनकी जल्द वापसी सुनिश्चित किया जाना है। इसमें कहा गया है कि उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग भी इसकी प्रक्रिया चला सकता है, जिससे श्रमिकों के बीच ज्यादा आत्मविश्वास आ सके।

आवश्यक जिंसों को लेकर फिक्की ने कहा है कि इस क्षेत्र में संयंत्रों व गोदामों पर ज्यादा मानव संसाधन लगाए जाने के लिए अधिक छूट की जरूरत है।

संगठन ने यह भी सुझाव दिया है कि उद्योग संगठनों को कंपनियों व उनके केंद्र, उनके विनिर्माण व गोदाम के स्थल, काम करने वाले कर्मचारियों की की सूची दाखिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

हर कंपनी के एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रबंधक को कर्मचारी को प्रमाणीकरण पत्र देने की अनुमति हो और उसे राज्य सरकार को निश्चित रूप से मानना चाहिए। संगठन ने यह भी सुझाव दिया है कि उद्योग संगठनों को कंपनियों व उनके केंद्र, उनके विनिर्माण व गोदाम के स्थल, काम करने वाले कर्मचारियों की की सूची दाखिल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हर कंपनी के एक केंद्रीय प्रशासनिक प्रबंधक को कर्मचारी को प्रमाणीकरण पत्र देने की अनुमति हो और उसे राज्य सरकार को निश्चित रूप से मानना चाहिए।

फिक्की ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के लिए कोविड 19 मानक तैयार करे, जिसमें गैर आवश्यक वस्तुओं की इकाइयों को भी काम की अनुमति हो।

विभिन्न क्षेत्रों के लिए फिक्की की मांग

- **खुदरा :** आवश्यक सेवाओं में लगे कर्मियों को कंपनी के पास के आधार पर आवाजाही की अनुमति हो
- **एफएमसीजी :** कॉर्पोरेट कार्यालय धीरे धीरे शुरू किए जाएं, किराना की दुकानों पर आपूर्ति की शृंखला बहाल की जाए
- **ई-कॉमर्स :** ई-कॉमर्स में काम करने वालों के लिए बीमा योजना की घोषणा हो
- **हेल्थकेयर :** ज्यादा, मध्यम और कम जोखिम के जिले व शहर चिह्नित किए जाएं
- **शिक्षा :** सभी कक्षाओं को दो पूल में बांटकर 1 मई और उसके बाद से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोले जाएं
- **होटल :** मेडिकल स्टाफ का जिन होटलों में पृथक्करण किया गया है, उन्हें काम करने की अनुमति दी जाए

एडीबी से भारत को मिलेंगे 2.2 अरब डॉलर

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 10 अप्रैल

एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं तैयार करने, देशबंदी के कारण कठिन दौर से गुजर रहे गरीबों और सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों की मदद करने के लिए भारत को 2.2 अरब डॉलर (करीब 16,000 करोड़ रुपये) देने का फैसला किया है।

बैंक के अध्यक्ष मासतसुगु असाकावा ने कहा, 'एडीबी भारत की आपातकालीन जरूरतों के लिए मदद करने को प्रतिबद्ध है। अब हम 2.2 अरब डॉलर की तत्काल सहायता देने की तैयारी कर रहे हैं, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में सहायता और वैश्विक महामारी के कारण हुई बंदी का आर्थिक असर गरीबों, अनौपचारिक कामगारों, सूक्ष्म, लघु और मझोले आकार के उद्यमों और वित्तीय क्षेत्र के लिए होगा।' उन्होंने कहा कि आगे जरूरत पड़ने पर एडीबी भारत को सहयोग और बढ़ाएगा। असाकावा ने कहा, 'हम भारत की जरूरतें पूरी करने के लिए वित्तपोषण के सभी विकल्पों पर विचार करेंगे, जो हमारे पास हैं। इसमें आपातकालीन सहयोग, नीति आधारित कर्ज और एडीबी फंड से जल्द धन जारी करने के लिए बजट समर्थन शामिल है।'

इस अवधि के दौरान निजी क्षेत्र की वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए एडीबी उनसे भी बातचीत कर रहा है। एडीबी के अध्यक्ष ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ फोन पर इस संबंध में बातचीत की। सीतारमण एडीबी की गवर्नर भी हैं। बैंक के अध्यक्ष ने सीतारमण को आश्वस्त किया कि वैश्विक महामारी कोरोनावायरस से भारत की लड़ाई में एडीबी हर तरह की मदद करेगा।

बातचीत के दौरान असाकावा ने कहा कि भारत ने इस महामारी से लड़ने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकालीन कार्यक्रम, कारोबारियों के लिए कर व राहत के अन्य कदम और 23 अरब डॉलर का आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा शामिल है। सरकार ने 26 मार्च को यह घोषणा गरीबों, महिलाओं, कामगारों को तत्काल लाभ पहुंचाने के लिए की थी, जो 3 सप्ताह की देशव्यापी बंदी से प्रभावित हुए है।

देशबंदी की मार सबसे ज्यादा गरीबों पर पड़ी है और एडीबी ने इनकी मदद करने के लिए हाथ बढ़ाए हैं। शुक्रवार को पुरानी दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान अपने रिक्शे पर बैठा रिक्शा चालक। दिल्ली में ज्यादातर रिक्शाचालक उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं और बंदी के कारण काम न होने की वजह से उन्हें कठिन दौर से गुजरना पड़ रहा है *फोटो-पीटीआई*

वैश्विक आर्थिक वृद्धि कमजोर रहने की वजह से भारत के कारोबार और विनिर्माण आपूर्ति शृंखला पर असर पड़ा है और पर्यटन व अन्य आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती आई है। इससे बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम दबाव में आ गए हैं और औपचारिक व अनौपचारिक श्रमिकों की रोजी रोटी देश भर में प्रभावित हुई है।

असाकावा ने कहा कि सरकार द्वारा घोषित नीतिगत कदमों से बहुत जरूरी राहत मिलेगी और हाशिये पर खड़े समाज के साथ साथ कारोबारियों को मदद मिलेगी और वह तेजी से कारोबार बहाल कर सकेंगे।

एडीबी ने 18 मार्च को विकासशील सदस्य देशों की जरूरतों को देखते हुए 6.5 अरब डॉलर के राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें भारत भी शामिल था। एडीबी ने कहा है कि वह आगे की स्थिति के मुताबिक और वित्तीय सहायता व नीतिगत सलाह देने को तैयार है।

निर्यात क्षेत्र में जा सकती हैं डेढ़ करोड़ नौकरियां

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 10 अप्रैल

इस समय 50 प्रतिशत से ज्यादा निर्यात ऑर्डर रद्द हो चुके हैं, जिसे देखते हुए निर्यात क्षेत्र में कम से कम 1.5 करोड़ नौकरियां जाने खतरा हो गया है। निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन (फियो) ने सरकार से कहा है कि अगर लक्षित आर्थिक राहत पैकेज नहीं दिया जाता है तो डेढ़ करोड़ नौकरियां जाने के साथ इस क्षेत्र की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) भी बढ़ सकती हैं।

वैश्विक महामारी
कोरोनावायरस

फियो के अध्यक्ष शरद कुमार सराफ ने कहा, 'हमारे पास बहुत कम ऑर्डर बचे हुए हैं। और अगर फैक्टरियों को न्यूनतम मजदूरों के काम शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाती है और इसे समय से नहीं लागू किया जाता है तो तमाम को अपूरणीय क्षति होगी और उद्योग बंदी की ओर चले जाएंगे क्योंकि उन्हें पहले से नियत लागत का भुगतान करना पड़ रहा है।' उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र का एनपीए बढ़ने का भी जोखिम है।

विश्व व्यापार संगठन ने बुधवार को कहा कि कोरोनावायरस के कारण आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ने से 2020 में वैश्विक कारोबार में 13 से 32 प्रतिशत की गिरावट आने की उम्मीद की जा रही है। डब्ल्यूटीओ ने कहा है कि मौजूदा गिरावट 2008-09 के वैश्विक आर्थिक संकट से कहीं बड़ा होगा। अपने वार्षिक कारोबारी सांख्यिकी और परिदृश्य रिपोर्ट में डब्ल्यूटीओ ने यह भी कहा है कि 2019 में भारत से विश्व के कुल निर्यात का 1.7 प्रतिशत निर्यात हुआ है, जबकि कुल आयात का 2.5 प्रतिशत आयात हुआ है। सराफ ने सरकार से अनुरोध किया कि वह तत्काल वित्तीय कदम उठाए और नीतिगत बदलाव कर उनका घाटा कम करे।

एनपीएस खाताधारकों को आंशिक निकासी की इजाजत मिली

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने शुक्रवार को कहा कि एनपीएस खाताधारकों को कोविड-19 के उपचार संबंधी खर्चों के लिए आंशिक निकासी की इजाजत होगी। पीएफआरडीए ने राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सभी अंशधारकों और खाताधारकों को संबोधित एक परिपत्र में कहा, 'भारत सरकार के निर्णय के मद्देनजर, जिसके तहत कोविड-19 को महामारी घोषित किया गया है, कोविड-19 को गंभीर बीमारी घोषित करने का निर्णय किया गया है, जो प्राणघातक है।'

उधर श्रम मंत्रालय ने कहा कि बंदी के दौरान ईपीएफओ ने 279.65 करोड़ रुपये के 1.37 लाख दावों का निपटान किया है। इन दावों का निपटान नए प्रावधान के तहत किया गया है। कोविड-19 संकट के दौरान अंशधारकों को राहत के लिए ईपीएफ योजना में संशोधन के जरिये यह प्रावधान किया गया है व अंशधारकों को पैसा मिलना शुरू हो गया है। *भाषा*

तिलहन और दलहन की दैनिक खरीद सीमा बढ़ी

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 10 अप्रैल

- प्रत्येक किसान के लिए दैनिक सीमा 25 क्विंटल से बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रतिदिन
- किसानों की रबी फसल की बिक्री में तेजी लाने के लिए कृषि मंत्रालय का कदम

किसानों को उनकी रबी की दलहन और तिलहन फसल की शीघ्र बिक्री में मदद के लिए कृषि मंत्रालय ने गुरुवार को दैनिक खरीद की सीमा बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान करने का फैसला किया है। फिलहाल यह सीमा 25 क्विंटल प्रतिदिन है। इसके अलावा खाद्य मंत्रालय ने एक अलग परिपत्र में राज्यों को केंद्रीय भंडार से कम दर पर खाद्यान्न लेने की मंजूरी दी है जो उसके द्वारा खुले बाजार में बिक्री वाली दर के मुकाबले कम है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि उन सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न का वितरण किया जा सके जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन उनके पास राज्यों द्वारा उनकी योजनाओं के तहत जारी राशन कार्ड हैं।

राज्य स्तर पर एनएफएसए के तहत करीब 81 करोड़ आबादी इसके दायरे में आती है, जबकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो अपने खर्च पर समान रूप से सस्ता राशन प्रदान करते हैं। गरीबों को अतिरिक्त पांच किलो खाद्यान्न वितरण किया जाना था, लेकिन लोगों द्वारा यह अतिरिक्त मात्रा नहीं लेने की खबरों के बाद यह घटनाक्रम सामने है। नए आदेश के अनुसार राज्य केंद्रीय भंडार से अपने नियमित आवंटन से अधिक मात्रा में 22 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर चावल और 21 रुपये की दर पर गेहूं ले सकते हैं। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि राज्य उन लोगों में वितरण करने के लिए सस्ती दर पर सीधे भारतीय खाद्य निगम गेहूं और चावल खरीदने को स्वतंत्र होंगे जिनके नाम लाभार्थी सूचियों में नहीं हैं।

बीएस बातचीत

आने वाले समय में और बढ़ेंगी राज्य की मुश्किलें

कोरोनावायरस महामारी के बीच दूसरे राज्यों से अलग बिहार सरकार की प्राथमिकता समय पर वेतन और पेंशन देने की होगी। इसी साल राज्य में विधानसभा चुनाव भी होना है। राज्य के उप मुख्यमंत्री **सुशील कुमार मोदी** ने **दिलाशा सेठ** के साथ बातचीत में कहा कि राज्य सरकार देशबंदी लागू होने से राज्य के बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए राहत का भुगतान भी करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 31 मार्च तक राजस्व को लेकर निश्चिंत थी लेकिन आगे मुश्किल दौर का सामना करना होगा। राज्य को उम्मीद है कि केंद्र सरकार एफआरबीएम सीमा बढ़ाकर 4 फीसदी कर देगी। बातचीत के प्रमुख अंश..

राज्य पहले से ही वित्तीय दबाव में हैं, ऐसे में कोविड से समस्या गहराने के आसार हैं। आप बिहार पर इसका क्या असर देखते हैं?

राज्य पहले से आर्थिक सुस्ती के कारण वित्तीय दबाव में हैं और अब कोविड का असर राज्यों को अप्रैल के बाद से सताना शुरू कर देगा। .आने वाले दिन बहुत मुश्किल होंगे।

राज्यों के लिए इस संकट से बाहर निकलने के लिए राजकोषीय दायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम सीमा में केंद्र से छूट मिलने को लेकर आप कितने आशान्वित हैं?

वर्ष 2009-10 में जब वित्तीय संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपनी चपेट में ले लिया था, तब एफआरबीएम सीमा में राहत देते हुए इसे 3 से 4 फीसदी किया गया था। 2010-11 में इसे घटकार 3.5 फीसदी किया गिया था। इस प्रकार तब राज्यों को दो वर्ष के लिए बढ़ी हुई सीमा की अनुमति मिली थी।

प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में भी बिहार ने मांग की थी कि राज्यों को जीडीपी के 1 फीसदी अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी जाए।

सच्चाई है कि पंद्रहवे वित्त आयोग ने राज्यों को बचाव खंड की अनुमति नहीं दी थी। 2019-20 में 3.5 फीसदी तक जाने की निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले राज्यों को 0.25 फीसदी और 0.25 फीसदी की अतिरिक्त सीमा मिली थी। हालांकि, 2020-21 में उन शर्तों को पूरा करने पर भी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। हमने मांग की है कि एफआरबीएम की सीमा को बढ़ाकर 4 फीसदी की जाए।

क्या इस पर केंद्र से आपको कोई प्रतिक्रिया मिली है?

केंद्र से अभी इस पर प्रतिक्रिया आना बाकी है लेकिन उन्होंने राज्यों की मांग सुनी है।

कोविड के कारण की गई बंदी से बिहार की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को लेकर आपका क्या अनुमान है?

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बिहार में राजस्व की वृद्धि 15 फीसदी रही थी। वस्तु एवं सेवा कर में बिहार ने 18 फीसदी की उच्चतम वृद्धि हासिल की थी। संयुक्त परिवहन ने 25 फीसदी वृद्धि हासिल की थी। लेकिन आने वाले दिन मुश्किल होंगे।

कुछ राज्य वेतन टालने पर विचार कर रहे हैं। इसको लेकर बिहार का क्या रुख है?

महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जो कर्मचारियों का वेतन आगे के लिए टाल रहे हैं, उनके उलट हमने तय किया है कि हम किसी तरह का वेतन नहीं टालेंगे। चूंकि कोविड से मुकाबला प्राथमिकता में है अत: समय पर वेतन और पेंशन दिया जाना चाहिए। हम इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। हम भुगतानों में किसी तरह का विलंब या कटौती नहीं करेंगे।

उस स्थिति में क्या आप 2020-21 में अपनी बाजार उधारी बढ़ाएंगे?

सामान्य तौर पर हम पहली तिमाही में उधारी नहीं लेते हैं, लेकिन इस बार जरूरत पड़ने पर हम पहली तिमाही में भी उधारी लेंगे। यदि केंद्र अतिरिक्त उधारी की अनुमति दे तो अच्छा रहेगा।

दूसरे राज्यों में फंसे बिहारी मजदूरों का खयाल कैसे रख रहे हैं?

बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो अपने प्रवासी मजदूरों का भी खयाल रख रहा है जिनमें राज्य से बाहर अटके श्रमिक भी शामिल हैं। दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों के भी खातों में 1,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है।

बीएस सूडोकू 3712

परिणाम संख्या 3711

						5		3
			1					
		6		2		9		
	8	4	5		7	1	6	
5		7		3				
					8			
8		3	9	7				4
4		2						
		1			3	7		

8	9	2	7	3	1	6	4	5
1	7	4	6	9	5	3	8	2
5	3	6	2	4	8	1	9	7
2	8	9	4	5	3	7	1	6
4	6	3	8	1	7	2	5	9
7	1	5	9	6	2	8	3	4
3	4	1	5	7	6	9	2	8
9	2	7	3	8	4	5	6	1
6	5	8	1	2	9	4	7	3

कैसे खेलें?

हर, रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मध्यम

★ ★ ★ ☆ ☆

कम टीडीएस वाली कंपनियों को आयकर विभाग से और राहत

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 10 अप्रैल

आयकर विभाग ने उन कंपनियों को और राहत दी है, जिनका स्रोत पर कर (टीडीएस) या स्रोत पर संग्रहीत कर (टीसीएस) कम है।

हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कम टीडीएस या टीसीएस के लिए जारी प्रमाणपत्रों की वैधता 3 महीने के लिए बढ़ा दी थी। कोविड-19 को देखते हुए सीबीडीटी ने 30 जून तक के लिए तिथि बढ़ाने का फैसला किया था।

अब विभाग ने कहा है कि वित्त वर्ष 21 के लिए नए सिरे से सीमा तय की जाएगी, भले ही पिछले प्रमाणपत्रों की वैधता 3 महीने के लिए बढ़ा दी गई है।

एकेएम ग्लोबल के पार्टनर अमित माहेश्वरी ने इसे साफ करते हुए कहा कि सामान्यतया जिन कंपनियों को यह डर होता है कि उनकी कुल कर देनदारी टीसीएस या टीडीएस से कम होता है, उन्हें राहत मिलेगी और उनका नकदी का प्रवाह बना रहेगा। उन्हें साल की आमदनी और मुनाफा विभाग को बताना होगा।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 13 अंक 44

माकूल वक्त पर

कोविड-19 महामारी नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के पहले साल को बचाने सही समय पर आई है। यह साल प्रतिकूल आर्थिक रुझानों के साथ शुरू हुआ था, अर्थव्यवस्था के गैर-सरकारी हिस्से की वृद्धि दिसंबर 2019 के पहले की दो तिमाहियों में महज तीन फीसदी ही रह गई थी। राजनीतिक तौर पर मोदी नागरिकता कानून में संशोधन के बाद देश भर में उपजे विरोध एवं धरनों के चलते एक बंद-गली की तरफ बढ़ चुके थे। इस कानून की कई राज्यों ने भी जोरदार मुखालफत की और दशकीय जनगणना भी खतरे में पड़ गई। लेकिन कुछ हफ्तों में ही पूरा विमर्श बदल चुका है। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग हट चुके हैं, राज्य सरकारें वित्तीय सहयोग की आस में केंद्र के आगे कतार में लगी हैं और सारी आर्थिक समस्याओं को अब आसानी से कोविड-19 के दरवाजे पर धकेला जा सकता है। कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा के दौरान संसद में नहीं दिखे प्रधानमंत्री अब हरेक कुछ दिन पर राष्ट्रीय टेलीविजन पर आकर नोटबंदी वाले अंदाज में बिना किसी पूर्व सूचना के लॉकडाउन की घोषणा करते और उपदेश सुनाते हुए दिख जाते हैं। वह वैश्विक पटल पर भी उसी तरह सक्रिय भूमिका में हैं, कभी अमेरिका तो कभी ब्राजील के राष्ट्रपति उन्हें जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। विपक्ष चारों खाने चित है। उसे इस संकट के समय खुद को राष्ट्रीय प्रयासों का अंग दिखाने के साथ आलोचना भी करनी है। मोदी जैसा चतुर नेता एक संकट में छिपा अवसर कभी नहीं गंवाता है और वह इसका इस्तेमाल अपनी छवि चमकाने में कर रहे हैं। पीएम-केयर्स फंड इसकी एक मिसाल है। यह डॉनल्ड ट्रंप से कुछ खास अलग नहीं है जिन्होंने कोविड महामारी का इस्तेमाल करते हुए अपने चुनौतीकर्ता जो बाइडन को टीवी स्क्रीन से दूर ही कर दिया है। हालांकि गलतियां हो रही हैं लेकिन नेता के इर्दगिर्द पूरे देश के खड़े होने पर इन आलोचनाओं से पार पाना आसान है। ट्रंप ने महामारी से निपटने में देर से कदम उठाने एवं अनाड़ीपन दिखाने को लेकर हो रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए चीन और विश्व स्वास्थ्य संगठन पर निशाना साधा है। वहीं मोदी ने लॉकडाउन की वजह से फंसे प्रवासी मजदूरों की समस्या पर उनसे माफी मांगी। बांग्लादेश और सिंगापुर जैसे देशों ने लॉकडाउन करने के पहले अपने नागरिकों को समय दिया था लेकिन मोदी तो सर्जिकल स्ट्राइक में यकीन रखते हैं।

साप्ताहिक मंथन

टी. एन. नाइनन

युद्धकाल में बड़े नेताओं की लोकप्रियता काफी बढ़ जाती है, खासकर अगर वे बहुत अच्छे वक्ता भी हों। चर्चिल ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपने फैसलों से नाकामी को गले लगाया लेकिन कुछ बेहतरीन भाषण भी दिए। अमेरिकी अर्थव्यवस्था भीषण आर्थिक मंदी (1929-33) से युद्ध संबंधी उत्पादन शुरू होने पर ही उबर पाई थी लेकिन इसका श्रेय रूजवेल्ट के 'न्यू डील' कार्यक्रम को दिया जाता है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने दूसरा राष्ट्रपति चुनाव 'आतंक के खिलाफ युद्ध' के नाम पर ही जीता था। यह युद्ध बहुत खराब मोड़ पर जाकर खत्म हुआ है लेकिन बुश तो अपने फार्महाउस में सुरक्षित हैं। लाल बहादुर शास्त्री भी एक नायक के तौर पर सामने आए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को रोक दिया था और नेहरू की तरह उन्हें चीन से शिकस्त नहीं खानी पड़ी थी। मोदी खुद को एक युद्धकालीन प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करने के लिए बेचैन हैं। पिछले साल बालाकोट एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल चुनाव का रुख अपनी तरफ मोड़ने के लिए बखूबी किया गया था जबकि हमने उस कोशिश में खुद से काफी कमजोर दुश्मन के खिलाफ अपना एक विमान भी गंवा दिया था। इस सर्जिकल स्ट्राइक के जरिये पुलवामा में हुए आतंकी हमले से पैदा हुए सुरक्षा नाकामियों के सवाल दरकिनार कर दिए गए। अब मोदी के सामने कहीं अधिक वास्तविक लेकिन अलग तरह का युद्ध है जिसकी तुलना उन्होंने महाभारत से की है। अगर आप मोदी के अगले कदम का अनुमान लगाना चाहते हैं तो वर्ष 2007 का उनका एक बयान याद करें। उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष को 'जन-आंदोलन' बनाने में महात्मा गांधी की भूमिका की तारीफ करते हुए कहा था कि वह विकास को ऐसा ही जन-आंदोलन बनाना चाहते हैं।

गैस सब्सिडी छोड़ने के लिए चलाए गए 'गिव इट अप' अभियान की ही तरह मोदी 'जनता कर्फ्यू' लागू कर और लोगों को थाली बजाने एवं दीया जलाने को कह इसे जन-आंदोलन की शक्ल देना चाहते हैं। हालांकि इनकी तुलना 'दांडी मार्च' से नहीं हो सकती लेकिन कोविड की तरह मोदी का काम भी अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच मुस्लिमों को अलग-थलग करने की कोशिश एक जन-आंदोलन में तब्दील हो चुकी है।

अजय मोहंती

लॉकडाउन समाप्त हो अथवा नहीं ?

यदि देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है तो इससे और अधिक मौतें हो सकती हैं। इस विषय पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं शंकर आचार्य

कोविड-19 के कारण लागू तीन सप्ताह का देशव्यापी लॉकडाउन 14 अप्रैल की मध्य रात्रि को समाप्त हो रहा है। सरकार को उससे कुछ समय पहले कुछ विकल्पों में से एक की घोषणा करनी होगी: (क) लॉकडाउन की अवधि में कुछ सप्ताह का इजाफा, (ख) लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और (ग) लॉकडाउन को तत्काल पूर्ण रूप से समाप्त करना। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत के बारे में मीडिया में आई जानकारी से संकेत निकला कि उनसे यह चर्चा की गई कि लॉकडाउन के दौरान लगे प्रतिबंधों को किस प्रकार चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए। अन्य खबरों के मुताबिक लॉकडाउन को कुछ सप्ताह आगे बढ़ाया जा सकता है। मेरा मानना है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।

कोविड-19 के खिलाफ इस जंग में लॉकडाउन चीन, अमेरिका और बड़े यूरोपीय देशों में स्वैच्छिक हथियार बना। दिलचस्प है कि जर्मनी और दक्षिण कोरिया ने लॉकडाउन को नहीं अपनाया जबकि वहां इस महामारी से होने वाली मृत्यु दर सबसे कम है। इन देशों और भारत के बीच कम से कम चार बड़े अंतर हैं जो भारत के लिए लंबे लॉकडाउन को वांछित नहीं बनाती। पहली बात तो यह कि भारत एक गरीब मुल्क है जहां औसत आय चीन की औसत आय के पांचवें हिस्से और यूरोप या अमेरिका की औसत आय के 20वें हिस्से के बराबर है। देश के 20 फीसदी परिवार गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। जबकि 20 से 30 प्रतिशत लोगों की हालत उनसे कुछ ही बेहतर है। इसका अर्थ यह है कि करीब आधी आबादी किसी तरह दिन काट रही है। मौजूदा लॉकडाउन जैसी स्थिति में उनके पास आय में आई कमी से निपटने का कोई जरिया नहीं है। लॉकडाउन बढ़ने पर वे अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरा नहीं कर पाएंगे।

दूसरी बात, देश की श्रम शक्ति का करीब 80 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में है। इनकी आय बहुत कम रहती है। यह प्राय: अनुशंसित न्यूनतम वेतन से भी कम रहती है। लॉकडाउन की स्थिति में जहां कम से कम आधी आर्थिक गतिविधियां ठप हैं, वहां रोजगार और आय के मोर्चे पर सबसे अधिक नुकसान कामगारों को ही उठाना पड़ा। टेलीविजन पर नजर आने वाले हजारों प्रवासी श्रमिक जो सैकड़ों मील चलकर अपने घरों को गए, वे इसे अच्छी तरह दर्शाते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकनॉमी के ताजा सर्वेक्षण से पता चलता है कि मार्च के आखिरी सप्ताह में बड़े पैमाने पर रोजगार की हानि और श्रम शक्ति भागीदारी में गिरावट देखने को मिली। चूंकि यह श्रम शक्ति मोटे तौर पर असंगठित क्षेत्र में है इसलिए उसे हर्जाना देना या सुरक्षित रखना भी मुश्किल है। सरकार की आय या खपत समर्थक योजनाओं का भी उन्हें लाभ नहीं मिलेगा।

तीसरी बात गरीब देशों की तरह भारत में भी कल्याण योजनाएं यूरोपीय शैली के राष्ट्रीय कल्याण ढांचे का विकल्प नहीं हैं। हमें उनकी तरह बेरोजगारी बीमा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा नहीं मिलती।

चौथा, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और सेवाओं की अमेरिका और यूरोप के देशों से तुलना नहीं की जाती। यह बेहद खराब है। उन देशों में लॉकडाउन के पीछे बुनियादी दलील यह थी कि इस अवधि का इस्तेमाल अस्पताल के बेड, वेंटिलेटर और पीपीई आदि खरीदने या कोविड-19 मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए इनकी बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए इनका निर्माण करने में किया जाएगा। निकट भविष्य में यानी एक डेढ़ साल में कोविड-19 का टीका बनने तक या इसका उपचार सामने आने तक यूं ही बच बचाकर रहना होगा। भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो कोविड-19 के उपचार के लिए इन सुविधाओं में इजाफा कर पाना काफी हद तक मुश्किल नजर आता है। देश में लॉकडाउन तीन सप्ताह चले या तीन महीने, हम जो चीजें 70 वर्ष में नहीं हासिल कर पाए वे कुछ सप्ताह में नहीं हासिल होंगी।

प्रश्न यह है कि मौजूदा लॉकडाउन से आर्थिक गतिवधियां ठप करने, व्यापक पैमाने पर रोजगार की हानि के अलावा क्या हासिल हो रहा है? कुछ बातें तो हो रही हैं। मसलन बीमारी का प्रसार धीमा पड़ा है। लॉकडाउन के कारण हमें अस्पताल सुविधाओं की उपलब्धता और गहन चिकित्सा के लिए जरूरी उपकरणों को जुटाने में मदद मिल रही है। स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और क्वारंटीन करने में आसानी हो रही है। दूसरा, इसके चलते लोग नाटकीय ढंग से अपने घर में सिमट गए हैं। इससे विभिन्न प्रकार की लागत में कमी आई है। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भी सामाजिक दूरी जैसे मानकों, बार-बार हाथ धोने, मास्क पहनने जैसी आदतें दीर्घकाल में काम आ सकती हैं। बड़े पैमाने पर लोगों के जमाव को भी कम किया जा सकता है। यह सही है कि भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में जहां तमाम लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं इसमें से काफी कुछ नहीं हो पाएगा। बहरहाल, हमें इन लाभों की भारी आर्थिक और मानवीय कीमत चुकानी पड़ सकती है।

लॉकडाउन करने वाले अमीर देशों में इसकी लागत और लाभ को लेकर बहस चल रही है। इसे मोटे तौर पर कोविड से होने वाली मौतों के कम होने और इसकी आर्थिक कीमत के संदर्भ में देखा जा रहा है। भारत के लिए ऐसी बहस बहुत सामान्यीकृत हो जाएगी। यह समझने की बात है कि दीर्घकालिक लॉकडाउन से मौतों की तादाद बढ़ेगी क्योंकि लोगों की आय समाप्त हो गई है और उन्हें पर्याप्त पोषण तथा विभिन्न बीमारियों मसलन टीबी, डायरिया, श्वसन समस्या, दिल की बीमारियों, मधुमेह आदि का उचित इलाज नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा भूख से भी लोगों की मौत होगी। लॉकडाउन में केवल जीडीपी का नुकसान नहीं होगा। बल्कि इस दौरान लोग कोविड से भी मरेंगे और दूसरी वजहों से भी। ज्यादातर मौतें गरीबों की होंगी। किसी को नहीं पता कि कितनी मौत होंगी। मेरा मानना है कि मौजूदा देशव्यापी लॉकडाउन को 14 अप्रैल के बाद नहीं बढ़ाया जाना चाहिए।

जैसा कि लगातार कहा जा रहा है, हमें यह भी आशा करनी चाहिए कि गर्मियां बढ़ने के साथ कोविड-19 वायरस कमजोर पड़ेगा।

(लेखक इक्रियर में मानद प्रोफेसर और भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार हैं। लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

लॉकडाउन में काम के साथ बढ़ गया टीवी की ओर रुझान

मीडिया मंत्र

वनिता कोहली-खांडेकर

लॉकडाउन के बीच में लोग किस तरह स्वादिष्ट पकवान बनाने में जुटे हुए हैं? कोरोनावायरस के प्रसार की वजह से देश भर में लागू हुए लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते में प्रवेश करने के साथ ही यह सवाल मुझे परेशान कर रहा है। दर्जनों मित्र एवं सहयोगी अपने ट्विटर, फेसबुक एवं व्हाट्सऐप खातों पर लजीज खानपान से संबंधित तस्वीरें एवं वीडियो पोस्ट कर रहे हैं और उनका यह बरताव मुझे उलझन में डाल रहा है। क्या उन्हें अपने घर की साफ-सफाई, बच्चों एवं बुजुर्गों की देखभाल और घर से ही काम नहीं करना होता है? और वे लोग थोड़ी-बहुत सब्जियों, दाल और चावल के अलावा बाकी सामान कहां से जुटा ले रहे हैं? सामान्य परिस्थितियों में मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। लेकिन हर दिन घर की साफ-सफाई, झाड़-पोछा और खाना पकाने के अंतहीन सिलसिले ने इस खुशी को छीन लिया है। खास तौर पर लॉकडाउन के शुरुआती 10 दिनों में तो इससे थोड़ी भी राहत नहीं मिल पाई क्योंकि दिल्ली के मेरे इलाके में तो बाहर से कुछ मंगाने का विकल्प ही नहीं था।

पिछले हफ्ते डोमिनोज ने होम डिलिवरी करनी फिर से शुरू की लेकिन वह भी गिने-चुने सामान की। अब तो करीब आधा दर्जन जगहों से संपर्क-रहित डिलिवरी होने लगी है। इसका मतलब है कि भुगतान केवल ऑनलाइन ही किए जा सकते हैं और डिलिवरी देने वाला व्यक्ति मास्क एवं ग्लव्स पहने हुए आएगा और आपकी कॉलोनी के मुख्य दरवाजे पर ही पैकेट देकर चला जाएगा। हमें भी खाने का वह पैकेट लेने के लिए मास्क पहने हुए अपने घर से बाहर निकलना होता है। इस सुविधा ने कुछ समय की बचत कर दी है लेकिन वह भी लगातार अपने पसंदीदा कार्यक्रम देखने के लिए काफी नहीं है।

इसी से मेरा दूसरा सवाल खड़ा होता है। अगर हम अपने घरों में रहते हुए दफ्तर का काम कर रहे हैं तो फिर टेलीविजन देखने वाले और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर एक साथ कई एपिसोड देखने (बिंज वॉचिंग) वाले दर्शकों की संख्या अचानक इतनी कैसे बढ़ गई है? देश भर में टीवी के कुल दर्शकों की संख्या कोविड-19 की वजह से हुई बंदी के दौरान (21-27 मार्च) 37 फीसदी तक उछल गई। टेलीविजन रेटिंग करने वाली संस्था ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (बार्क) ने यह आंकड़े 11-31 जनवरी की तुलनात्मक संख्या के आधार पर जारी किए हैं। एक और नजरिये से देखें तो वर्ष 2018 की तुलना में टीवी के दर्शक 2019 में 38 फीसदी तक बढ़ गए हैं। पहले एक व्यक्ति औसतन रोजाना तीन घंटे 46 मिनट तक टीवी देखता था लेकिन कोविड-19 के बाद वह संख्या बढ़कर चार घंटे 38 मिनट हो चुकी है। इसी के साथ रोजाना टीवी देखने वाले दर्शकों की औसत संख्या भी 67 करोड़ से बढ़कर 62.2 करोड़ हो गई।

सवाल यह है कि टीवी देख रहे ये लोग कौन हैं? सबसे तेज वृद्धि (47 फीसदी से भी अधिक) घरों के भीतर रहने को मजबूर 2-14 साल के बच्चों के बीच हुई है। दूसरी तीव्र वृद्धि (36 फीसदी) 31-40 और 41-50 साल की उम्र वाले दर्शकों में देखी गई है। ये कामकाजी लोग हैं जो लॉकडाउन के चलते घरों के भीतर हैं। इनमें कारोबारी, दुकानदार, अध्यापक, सरकारी कर्मचारी, घरेलू नौकर, लेखक, फिल्मकार, कंपनियों के कर्मचारी-अधिकारी सभी तरह के लोग हैं। खास बात यह है कि दर्शक संख्या में यह बढ़ोतरी सभी तरह के आर्थिक समूहों में देखी जा रही है। उच्च-आय वर्ग एवं अंग्रेजी भाषी लोगों में भी टीवी देखने की प्रवृत्ति खूब बढ़ी है, हालांकि उनका आकार छोटा है।

इसका मतलब एकदम साफ है कि घरों के भीतर रहने के लिए मजबूर सभी तरह के भारतीय इन दिनों टीवी सेट के आगे ही बैठे रह रहे हैं। यही कारण है कि लॉकडाउन के बाद प्राइम टाइम से अलग स्लॉट में भी टीवी दर्शकों की संख्या में 71 फीसदी की जबरदस्त उछाल देखी गई है।

हालांकि इसका एक पहलू यह भी है कि टीवी दर्शकों में हुई बढ़ोतरी की वजह से समाचार चैनल देखने वाले दर्शकों की तादाद कोविड महामारी से उपजी अनिश्चितता के दौर में सात फीसदी से बढ़कर 21 फीसदी तक पहुंच चुकी है। समाचार के नाम पर परोसे जा रहे कार्यक्रमों को देखने वालों में बच्चों की भी मौजूदगी है।

कुछ ऐसा ही परिदृश्य ऑनलाइन जगत का भी है। महामारी से जुड़ी खबरों के बारे में पढ़ने के लिए समाचारों की वेबसाइट एवं ऐप का इस्तेमाल करने वाले मार्च में 61 फीसदी तक बढ़ गए हैं। कॉमस्कोर के आंकड़े बताते हैं कि फरवरी की तुलना में मार्च में सामान्य खबरों की वेबसाइट एवं ऐप का इस्तेमाल बढ़ा है। हालांकि स्ट्रीमिंग सेवाओं के बारे में कोई सटीक आंकड़ा अभी तक उपलब्ध नहीं है।

इसी से हम अपने अंतिम लेकिन सबसे अहम सवाल तक पहुंचते हैं। अगर आपको कुछ खाली वक्त मिलता है तो आप क्या देखते हैं? मेरे पसंदीदा टीवी शो में 'द क्राउन ऐंड शरलॉक' (नेटफ्लिक्स), 'डाउनटाउन ऐबी' और 'द मार्वलस मिसेज मैसल' (एमेजॉन प्राइम वीडियो) आते हैं जिन्हें मैं बार-बार देखती हूं। फिर द लाउडेस्ट वॉयस (हॉटस्टार), ब्रॉडचर्च और क्रिमिनल (नेटफ्लिक्स) भी हैं। अगर आपकी पसंद डॉक्यूमेंट्री या डॉक्यू-सीरीज हैं तो फिर आप बिल गेट्स के बारे में 'इनसाइड बिल्स ब्रेन', खानपान से संबंधित 'शेफ्स टेबल' और भगवान रजनीश के बारे में एमी अवॉर्ड से सम्मानित शो 'वाइल्ड वाइल्ड कंट्री' देख सकते हैं। ये सारे शो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध हैं।

नए ड्रामा शो के तौर पर मैंने हाल ही में द इंगलिश गेम देखना शुरू किया है लेकिन लॉकडाउन खत्म होने और सामान्य जिंदगी शुरू होने के बाद ही बिंज वॉचिंग का वक्त मिल पाएगा। उसके बजाय मैंने 'द बिग बैंग थिअरी' की तरफ अपना ध्यान भटकाने की कोशिश की है। यह रोजाना 20 मिनट तक हंसी के सफर पर ले जाता है और मेरे सारे सवालों के जवाब भी देता है।

कानाफूसी

सुरक्षित जेल

बंबई उच्च न्यायालय का कहना है कि आजकल बाहर के हालात से तो जेल की जिंदगी बेहतर है। मुंबई के उपनगरीय इलाके घाटकोपर के एक निवासी ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए अस्थायी जमानत मांगी थी। न्यायालय ने इससे इनकार करते हुए कहा कि वह उस शख्स को कोरोनावायरस के खतरे में नहीं डालना चाहता है। न्यायमूर्ति जीएस पटेल ने पिछले 18 महीने से नवी मुंबई की तालोज जेल में बंद हत्या के आरोपी जितेंद्र मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जेल की स्थिति शहर से काफी बेहतर है। न्यायमूर्ति पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई करते हुए कहा कि कोविड-19 से निपटने के लिए जेल में नगरपालिका खासकर वर्ली नाका से ज्यादा बेहतर सुविधाएं हैं। मध्य मुंबई का वर्ली कोलीवाड़ा इलाका शहर में कोविड-19 का हॉटस्पॉट बनकर उभरा है।

बढ़ता दोस्ताना

उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा और बसपा के बीच बढ़ रही नजदीकियां आजकल लखनऊ में चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल बसपा प्रमुख मायावती ने अपने विधायकों को कोरोनावायरस के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोग करने को कहा था। इसके बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मायावती को फोन करके उन्हें इसके लिए धन्यवाद दिया। बसपा प्रमुख ने केंद्र और राज्य की सरकारों को कोई भी फैसला लेते समय गरीबों की मुश्किलों को ध्यान में रखने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मिलकर काम करना चाहिए। बसपा प्रमुख ने साथ ही भरोसा दिया उनकी पार्टी सरकार के उन सभी प्रयासों का समर्थन करेगी जिनमें बिना किसी भेदभाव के जनकल्याण की भावना होगी।

आपका पक्ष

लॉकडाउन की अवधि में संशय

लॉकडाउन की अवधि जैसे-जैसे खत्म होने के करीब आ रही है केंद्र तथा कुछ राज्य सरकारें इसकी अवधि को बढ़ाने के पक्ष में दिखाई दे रही है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के आंकड़े कम नहीं हो रहे हैं। अगर पाबंदी हटती है तब संक्रमण बढ़ने का खतरा भी बढ़ सकता है। अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ेगा। सरकार को 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा के वक्त उम्मीद थी कि कोरोनावायरस का संक्रमण काफी हद तक नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन लोगों द्वारा कड़ाई से नियमों का पालन नहीं करने की वजह से लॉकडाउन के संतोषजनक परिणाम नहीं निकले हैं। इस वजह से सरकारों के बीच असमंजस की स्थिति बनी है। अगर लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई भी गई तो

सकारात्मक निर्णय निकलने की गारंटी किसी के पास नहीं है। देश में एक लाख लोगों के पीछे मात्र 192 पुलिस बल है तथा इतनी कम संख्या से लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करने की उम्मीद बेमानी लगती है। लोगों की राशन की दुकानों में लंबी कतार देखने को मिल रही है। इस वजह से संक्रमण का दायरा बढ़ने का खतरा बढ़ रहा है। लोक कल्याण राज्य सबसे पहले अपने जनता के स्वास्थ्य के बारे में सोचता है तथा हमारा देश एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसलिए इसके मद्देनजर सरकार लॉकडाउन की अवधि बढ़ा सकती है। वहीं कोरोना संक्रमण का उपचार खोजे बगैर लॉकडाउन के सिवा कोई विकल्प भी नहीं है। इससे जनता की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि लॉकडाउन का पालन करें एवं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपना सहयोग दें। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार को संक्रमण रोकने तथा अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए नए उपायों तथा विकल्पों को तलाशना चाहिए ताकि कोरोना के बाद आने वाली मुश्किलों से संभला जा सके।

निशांत महेश त्रिपाठी, नागपुर

लॉकडाउन के बाद हॉटस्पॉट बनाकर सरकार कड़ाई कर रही

लॉकडाउन का फायदा उठाएं छात्र

भारत इस समय वैश्विक महामारी कोरोना से जूझ रहा है। हमारे देश की केंद्र और राज्यों सरकारों ने कोरोनावायरस की कड़ी को तोड़ने के लिए लॉकडाउन किया हुआ है। लगभग सभी देशवासी इस लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं लेकिन लॉकडाउन के कारण देश के उद्योग, कारोबार और बहुत कुछ बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। यहां तक कि बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। हालांकि कुछ स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं हो। ऐसे लोगों के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में भी बाधा पड़ रही होगी। लेकिन छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

नई दिल्ली | 11 अप्रैल 2020 शनिवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

कोरोना : अभी के फैसले दिलाएंगे भविष्य में राहत

यह वक्त अगले दो साल तक सोच-समझकर उठाए जाने वाले फैसलों का है जो भविष्य में निजी निवेश बढ़ाने का आधार तैयार करेंगे

विजय केलकर और अजय शाह

महामारियां हमें भयाक्रांत कर सकती हैं। वर्ष 1918 में 'बॉम्बे फीवर' ने भारत में दस्तक दी थी और देश की करीब पांच फीसदी आबादी का सफाया कर दिया था। उसकी तुलना में कोविड-19 अधिक गंभीर बीमारी नहीं है लेकिन इसके पिछले 102 वर्षों की सबसे घातक महामारी बनने की पूरी आशंका है। ऐसे आघात किसी भी राज्य की क्षमता का परीक्षण करते हैं। भारतीय राज्य को इस महामारी से लड़ने के लिए अपने शासन के तीनों स्तरों पर क्षमता इस तरह बढ़ानी होगी कि नए नीतिगत उपायों का खाका खींचकर उन्हें अमल में लाया जा सके। इस जंग में स्वास्थ्य, वृहद-अर्थव्यवस्था और वित्त की समस्याएं बहुत गहराई से एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस लेख में हम इन तीनों क्षेत्रों से संबंधित ज्ञान के आधार पर आगे के लिए नीतिगत नजरिया विकसित करने का प्रयास करेंगे।

लॉकडाउन का तात्कालिक प्रभाव

बाजार अर्थव्यवस्था में विभिन्न उद्योगों के बीच बेहद जटिल अंतर्संबंध होते हैं। हरेक 'आवश्यक' आउटपुट के लिए अनगित 'गैर-जरूरी' इनपुट की जरूरत होती है। मसलन, फेस मास्क या वेंटिलेटर बनाने के लिए ही जटिल संयोजन वाले इंजीनियरिंग उपकरणों की जरूरत होती है। आने वाले दिनों में जरूरी एवं गैर-जरूरी दोनों तरह के उत्पाद बनाने वाले कई कारखानों में उत्पादन बाधित हो सकता है। इससे तैयार माल कम होते जाएंगे, आपूर्ति श्रृंखला टूटने लगेगी और फिर उत्पादन भी ठप पड़ने लगेगा। करीब एक चौथाई बड़ी कंपनियों के लिए भी एक महीने तक राजस्व नहीं मिलने से कामकाज चलाना मुश्किल होने लगेगा। खाने-पीने के सामान की आपूर्ति श्रृंखला खास तौर पर अहम है। खास तरह के 'जरूरी' उत्पादों (मसलन, सब्जियां या दूध) की उपलब्धता भी जगहों पर समस्या बन सकती है। ऐसे में खतरा इस बात का है कि एक बार फिर से साठ और सत्तर के दशकों का मुनाफाखोरी एवं जमाखोरी वाला दौर न आ जाए। ऐसे माहौल में तमाम कंपनियां एवं कामगार खर्चों में कटौती करेंगे जिससे अर्थव्यवस्था में मांग गंभीर रूप से प्रभावित होगी। आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने और मांग कम होने के कारक एक-दूसरे पर असर डालेंगे और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में गिरावट आएगी। आय को लगने वाला झटका लोगों की सेहत पर भी असर डालेगा और पिछली आपदाओं के वृहद-अर्थशास्त्रीय अध्ययन से यह साबित भी होता है।

2020 और 2021 की तैयारी

हमें कोविड-19 को महज तीन हफ्ते की समस्या के तौर पर नहीं देखना चाहिए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी भारत में संक्रमित लोगों की तादाद काफी होगी। सितंबर 2008 के लीमैन संकट ने जिस तरह 2009 और 2010 तक अपना असर दिखाया था, उसी तरह कोविड-19 से उपजे हालात भी 2020 और फिर 2021 तक कमोवेश बने रहने वाले हैं। नीति-निर्माताओं, कंपनियों, स्वास्थ्य देखभाल से जुड़े लोगों और आम इंसान, हर किसी को एक नव-सामान्य की लय विकसित करने की जरूरत है। वह ऐसी सामान्य परिस्थिति होगी जिसमें बहुतों के बीमार पड़ने से सामाजिक दूरी बरतना आम होगा और वृहद-आर्थिक एवं वित्तीय प्रणाली में खासी मुश्किलें होंगी। असामान्य आचरण से थकान पैदा होगी और इसे लंबे समय तक कायम नहीं रखा जा सकता है। हम सभी को एक नया सामान्य हासिल करने और जीवनशैली एवं आजीविका को लेकर टिकाऊ नजरिया अपनाने की जरूरत है।

आज हमें अर्थव्यवस्था के संबंध में सबसे अहम सवाल यह पूछना चाहिए कि महामारी का प्रकोप खत्म होने के बाद वी-आकार वाली रिकवरी के लिए खुद को कैसे तैयार किया जाए? हमें आज के हरेक नीतिगत कदम को इस नजरिये से देखना चाहिए कि क्या उससे 2020 और 2021 में एल-आकार वाली रिकवरी की राह तैयार होगी या फिर वी-आकार वाली रिकवरी का खाका बनेगा?

सही संतुलन की तलाश

सामाजिक दूरी का बेहतर स्वरूप कोविड-19 के स्वास्थ्य दुष्प्रभावों और सामाजिक दूरी के स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी प्रभाव के बीच की दुविधा से उपजता है। हम जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होने और आजीविका को तुलनात्मक रूप से कम अहमियत वाली गतिविधियों में लगातार कमी को अहम मानते हैं। धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट-पब, गणतंत्र दिवस परेड जैसी जगहें इस श्रेणी में आती हैं। इस तरह अगले दो साल भारत के भीड़-भाड़ वाले समारोहों के लिए काफी खराब नजर आ रहे हैं। सामाजिक दूरी का सटीक डिजाइन स्थानीय स्वरूप का होगा जो वहां की गतिविधियों के स्वास्थ्य प्रभावों, मौजूदा खतरे के आकलन और आर्थिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाएगा। ऐसे फैसले देश भर से जुटाई गई बौद्धिक जानकारी पर आधारित भले हों लेकिन उन्हें विकेंद्रित ढंग से ही आकार दिया जाना चाहिए। कोविड-19 युवा लोगों के लिए सापेक्षिक तौर पर अधिक गंभीर नहीं है। इस महामारी की मृत्यु दर 50 साल से कम उम्र वाले लोगों में कम है। एक बार इस बीमारी से उबर जाने के बाद जिंदगी भर के लिए उस व्यक्ति में प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है और ऐसे लोगों की संख्या समय के साथ बढ़ती जाएगी। वहीं इस वायरस से अब तक संक्रमित नहीं हुए बुजुर्गों को संक्रमण के जोखिम से बचे रहने की जरूरत है।

यह अर्थव्यवस्था में सामान्य स्थिति की बहाली की एक रणनीति दर्शाता है। हमें युवाओं को फिर से कामकाजी स्थिति में ले जाने की जरूरत है और सबसे जोखिम वाले काम में प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों को लगाया जाए। यह सजगता जरूर रखनी होगी कि बुजुर्गों पर खास ध्यान दिया जाए और बाहर निकले युवा इस बीमारी को अपने साथ रहने वाले बुजुर्गों तक न लेते जाएं। मई-अगस्त 2019 के आंकड़ों के मुताबिक, भारत की कुल आबादी में 50 साल से कम उम्र वाले लोग 81 फीसदी हैं। श्रमशक्ति में 75 फीसदी लोग 50 साल से कम उम्र के हैं। इस तरह हम लॉकडाउन की स्थिति से उस ढांचे की तरफ बढ़ सकते हैं जिसमें बुजुर्ग अत्यधिक सावधानी बरतें और बाकी लोग अर्थव्यवस्था को फिर से चलाएं। महिलाओं के बीच 16-50 उम्र वाली महज 8.8 फीसदी संख्या ही काम कर रही है लिहाजा इस समूह में काम पर जाने की गुंजाइश काफी अधिक है। भारत की स्थिति सर्वाधिक उन्नत देशों से अलग है और हमें अपने हालात पर बुनियादी उसूलों के हिसाब से गौर करना चाहिए।

जन स्वास्थ्य वक्त की जरूरत

शिनाख्त-परीक्षण-अलगाव-इलाज की पुरानी शैली वाली स्वास्थ्य मशीनरी की बड़े पैमाने पर जरूरत है। जन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को संक्रमित व्यक्ति के सभी संपर्कों तक पहुंचना होता है और फिर बड़े पैमाने पर परीक्षण की जरूरत होती है। उनमें से पॉजिटिव पाए जाने वाले लोगों को अलग-थलग करना होता है क्योंकि वे बीमारी दूसरों तक फैला सकते हैं। हालांकि 95 फीसदी संक्रमित लोगों में सीमित असर ही होता है जबकि बाकी पांच फीसदी लोगों को गहन इलाज की जरूरत होती है। उनमें से भी अधिकतर लोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन भारत में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत सीमित हैं लिहाजा चंद हफ्तों में ही हमें इस काम को बड़े स्तर पर करने की क्षमता तैयार करनी होगी।

जब संक्रमण व्यापक हो तो पूर्ण बंदी से हासिल आंशिक लाभ भी बड़े लगते हैं लेकिन भारत में अभी वैसी स्थिति नहीं है। फिर भी लॉकडाउन लागू करने के पीछे यही सोच है कि इन तीन हफ्तों का इस्तेमाल स्वास्थ्य नीति को चालू अवस्था में लाने और शिनाख्त-परीक्षण-अलगाव-इलाज की मशीनरी को बढ़ाने एवं गुणवत्ता सुधारने में किया जा रहा है। लेकिन इतने कम समय में राज्य की जन स्वास्थ्य क्षमता को बेहतर कर पाना बेहद मुश्किल काम है। इटली की आपदा एजेंसी के प्रमुख ने कहा भी है कि इस वायरस की रफ्तार हमारी नौकरशाही से कहीं तेज है। जन स्वास्थ्य की इस मुश्किल घड़ी में राज्यों का प्रदर्शन भी अलग है। केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्य बाकियों से बेहतर काम कर रहे हैं। लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में जन स्वास्थ्य क्षमता को तत्काल सुधारने की जरूरत है। वैसे इन राज्यों में युवा आबादी का बड़ा अनुपात राहत की बात हो सकती है।

ऐसी स्थिति में निजी क्षेत्र को शामिल करना बेहद जरूरी है। परीक्षण, आईसीयू और वेंटिलेटरों की मौजूदगी के मामले में निजी अस्पताल कहीं आगे हैं। इसके लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) करारों की जरूरत है ताकि परीक्षण उपकरणों के निजी उत्पादन एवं इलाज के लिए सार्वजनिक फंड का इंतजाम किया जा सके। खरीदी का काम अनुबंध प्रणाली के जरिये किया जाना चाहिए जिसमें निजी फर्मों से खरीद को वरीयता हो ताकि वे अपनी क्षमता बढ़ाएं। अगर हम भाग्यशाली हुए तो तेज धूप और बढ़ती गर्मी में महामारी का प्रसार धीमी गति से होगा जिससे हमें थोड़ा अतिरिक्त समय मिल जाएगा। इस समय का इस्तेमाल संक्रमित लोगों की शिनाख्त, उनके परीक्षण, अलग-थलग रखने और इलाज की क्षमताएं बढ़ाने में किया जाना चाहिए। इसी तरह खुशकिस्मती से शायद तब तक कोई वैक्सीन या इलाज भी सामने आ जाए। हमें इनका बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए भारतीय औषधि उद्योग को पूरी तरह तैयार रखना होगा ताकि स्वास्थ्य प्रणाली देश भर में इन्हें लागू कर सके।

1 फीसदी दबाव, 99 फीसदी आग्रह

नागरिकों की नजर में भारतीय राज्य की विश्वसनीयता कम है और यह कोई नई बात नहीं है। वर्ष 1897 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा था कि तमाम लोग दूसरी जगह पर रखे जाने के बजाय प्लेग से मर जाना अधिक पसंद करेंगे। दरअसल जब भी जन स्वास्थ्य बेहतर काम करता है तो वह एक फीसदी दबाव और 99 फीसदी आग्रह पर टिका होता है। अगर अधिक दबाव डालने का तरीका अपनाया जाता है तो लोकसेवक लोगों का भरोसा खो देते हैं। जब भी राज्य अधिकारवादी रुख अपनाता है तो जन स्वास्थ्य गतिविधियों को नुकसान पहुंचता है। सामाजिक दूरी, परीक्षण, अलगाव, टीकाकरण, दवाएं एवं जुटान संबंधी आंकड़े के लिए लोगों के भरोसे की जरूरत होती है। यह भरोसा हासिल करने के लिए जन स्वास्थ्य में नीतिगत कदमों के जरिये लोकतांत्रिक वैधता हासिल की जा सकती है। बाकी 99 फीसदी लोगों को मनाने के लिए विशेषज्ञता, पारदर्शिता, परामर्श, दबाव के बजाय सेवा की संस्कृति का सहारा लिया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय साहित्य में एक सुस्थापित तथ्य है कि उदारवादी लोकतंत्र महामारियों की चपेट में आने पर बेहतर तरीके से निपटते हैं। मसलन, हम चीन में यह देख चुके हैं कि सशक्त राज्य बल-प्रयोग की व्यवस्था किस कदर नाकाम रही है। भारत में लोग अपने स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड राज्य को देने में हिचक रहे हैं क्योंकि उन्हें इस आंकड़े के सरकारी इस्तेमाल पर कोई संरक्षण नहीं हासिल है। इस वायरस से जंग लड़ने का सबसे कारगर हथियार व्यक्तिगत एजेंसी, ठोस सूचना का सृजन एवं प्रेषण, बौद्धिक विमर्श, चर्चा, आलोचना और नियंत्रण एवं संतुलन है।

राज्य को लेकर भरोसे का भाव और सामाजिक एकता महामारी से मुकाबले में बड़ी ताकत साबित होती है। सामाजिक समरसता एवं राष्ट्रीय एकता के उच्च स्तर को बनाए रखने वाले कदमों से निश्चित तौर पर फायदा होगा।

महामारी अधिनियम 1897 एक औपनिवेशिक कानून है जिसमें नियंत्रण एवं संतुलन का अभाव है। हमें इस कानून को अलविदा कहते हुए संविधान एवं नागरिक स्वतंत्रता के बुनियादी उसूलों के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहरानी चाहिए।

बाजार की मजबूती

भारतीय राज्य की पहली प्रतिक्रिया कमान एवं नियंत्रण की होती है यानी पाबंदियों, मूल्य नियंत्रण, सीमापार आवाजाही पर रोक और लोगों को घर के भीतर सीमित रखने के तरीके। अनुदार गतिविधियों में संलिप्त होने पर अधिकारियों को होने वाली शर्मिंदगी आतंकी वारदात या महामारी की स्थिति में लुप्त हो जाती है। केंद्रीय नियोजन की ललक पैदा होती है, सरकार अर्थव्यवस्था को लेकर अनगिनत निर्देश जारी करती है और अचानक पैदा हुई समन्वयकारी नाकामियों को दूर करने की कोशिशें होती हैं। जब अर्थव्यवस्था कहीं छोटी एवं सरल थी और केंद्रीय नियोजन के लिए संस्थागत एवं बौद्धिक ढांचा कहीं अधिक मजबूत था तब भी कमान एवं नियंत्रण अमूमन नाकाम ही रहा। मौजूदा हालात में अर्थव्यवस्था अधिक जटिल है और सरकार के लिए इसकी निगरानी कर सकने वाले संगठन बनाना और उत्पादन के बारे में निजी क्षेत्र को निर्देश दे पाना लगभग नामुमकिन है।

मास्क की कीमतों में हुई बढ़ोतरी दिखाती है कि बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था किस तरह से संदेश भेजती है और तमाम निजी फर्में मास्क के उत्पादन में लग जाते हैं। अगर राज्य की बाध्यकारी शक्ति का इस्तेमाल कीमत तय करने में किया जाए तो हम इस आपूर्ति प्रतिक्रिया से वंचित हो जाएंगे। तार्किक इंसानों के बुनियादी भावों से मुकाबले के बजाय कीमत व्यवस्था की नीति तैयार करें और 20 फर्मों को 10-10 लाख मास्क की आपूर्ति के लिए निविदा जारी करें। ये फर्में कच्चे माल, लॉजिस्टिक एवं उत्पादन की समस्याएं दूर कर देंगी जो सरकार कभी नहीं कर सकती है। बाजार अर्थव्यवस्था की जटिल आत्म-व्यवस्था प्रणाली कुछ मामलों में बाधित हुई है और इसके सुधार का सबसे अच्छा तरीका यही है कि फर्में अपना हित देखते हुए खुद तय करें कि उन्हें आपूर्ति श्रृंखलाओं और कारोबार संबंधों को किस तरह बहाल करना है। निजी क्षेत्र लाभ की तलाश में इन समस्याओं को दूर करने के लिए ऑर्गेनिक स्तर पर काम करेगा। आत्म-व्यवस्था प्रणाली जानकारी जुटाने, दोतरफा लाभकारी सौदे करने और उत्पादन के मामले में सबसे अच्छी है। स्वास्थ्य देखभाल में जरूरत यह है कि टेस्टिंग एवं स्वास्थ्य देखभाल में निजी क्षेत्र के हितों को जगाया जाए। आउटपुट बढ़ाने और अचानक मांग बढ़ने पर विकल्प बढ़ाने का इकलौता रास्ता निजी क्षेत्र ही है। निजी क्षेत्र को निर्देशित करना या कीमत-सीमा तय करने का असर उलटा ही होगा। निजी क्षेत्र को अनुबंध करने के लिए स्वैच्छिक रूप से राजी करने का सम्मानजनक तरीका अधिक कारगर होगा। इसके लिए नीति-निर्माताओं को ठोस अनुबंध तैयार करने होंगे और रुचि रखने वाली फर्मों को उसके लिए बोली लगाने का मौका देना चाहिए।

वृहद-आर्थिक एवं वित्तीय नीति की समस्याएं

1. वृहद-आर्थिक एवं वित्तीय स्थिति काफी चिंताजनक है। कोविड-19 महामारी और लॉकडाउन की दोहरी मार झेल रहे हैं। विश्व अर्थव्यवस्था सिकुड़ चुकी है। हालात और भी बुरे हो सकते हैं, जैसे विदेशों में काम कर रहे भारतीय नागरिक स्वदेश लौटने को मजबूर हो जाएं या देश की वित्तीय स्थिति पर नई मार पड़े।

2. वृहद-आर्थिक एवं वित्तीय नीति का बेहद अहम काम एल-आकार वाली रिकवरी के बजाय वी-आकार वाली रिकवरी के अनुकूल हालात पैदा करना होना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार आर्थिक नीति की जरूरत है। हमेशा ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि बड़ी विपदा के समय नियम-कायदे से अलग हटकर व्यावहारिक काम करने चाहिए। हालांकि ऐसे उपाय वायरस का दंश खत्म होने के बाद हमें ही सताएंगे।

3. भारत में वृहद-आर्थिक नीति के मोर्चे पर अधिक उठापटक की गुंजाइश कम है क्योंकि हम पहले ही एक बड़े राजकोषीय घाटे और कमजोर मौद्रिक नीति अंतरण से गुजर रहे हैं। मसलन, जर्मनी लंबे समय से प्रभावी राजकोषीय नीति पर चलता रहा है जिससे कोविड-19 से जंग में वह जीडीपी के 10 फीसदी का प्रावधान कर पाया है। भारत के राजकोषीय संस्थान इतने व्यवस्थित नहीं हैं कि किसी संकट के समय बड़े घाटे से निपटने के लिए प्राथमिक अधिशेष का संचालन कर सकें और ऐच्छिक कर्जदाताओं से उधार ले सकें। इसी तरह अनुमानित मुद्रास्फीति में कमी आने पर आरबीआई को ब्याज दरों में कटौती करनी चाहिए लेकिन वित्तीय आर्थिक नीति की समस्याओं को देखते हुए इसका अर्थव्यवस्था पर असर कम होगा। यानी हमें वृहद-आर्थिक नीति से बहुत अपेक्षा नहीं पालनी चाहिए।

4. कुछ बैलेंस-शीट आधारित कर्जदाता स्वस्थ हैं और यह समय उनका फायदा बढ़ाने वाला है। लेकिन कई ऋणदाता स्वस्थ नहीं हैं और आगे चलकर उन्हें गहरे तनाव का सामना करना पड़ेगा।

5. निजी क्षेत्र इस बात को लेकर चिंतित है कि नीति-निर्माता किस हद तक जाएंगे। नियमों एवं विवेकाधिकार के बीच तनाव होने पर भारतीय राज्य अक्सर नियमों को कम तवज्जो देता है। इस राह पर चले तो नीतिगत अनिश्चितता बढ़ेगी और रिवकरी में मुश्किल होगी। जब हम महामारी को लेकर उठाए गए कदमों को एक पूर्वानुमेय एवं विधि के शासन के धरातल पर रखते हैं तो अनिश्चितता घटती है और निजी निवेश को बढ़ावा मिलता है।

6. भारत ने 2008 के वित्तीय संकट के समय जो वृहद-आर्थिक एवं वित्तीय नीति संबंधी कदम उठाए थे, उससे काफी कुछ सीखना है। वित्तीय बाजारों का कामकाज एवं अटकलों पर आधारित कारोबार बंद करने या सीमित करने की आवाजें उठने लगी हैं। लेकिन 2008 की तरह सही रास्ता यही है कि बाजारों के कामकाज में दखल न दिया जाए।

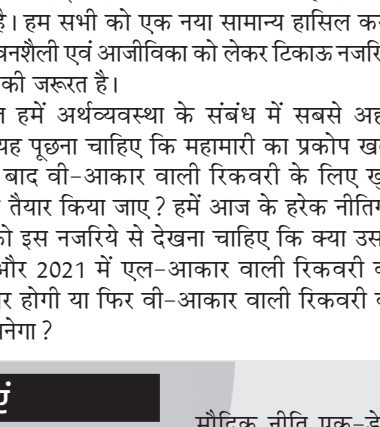

जब एक नियामकीय कदम से वित्तीय बाजार की तरलता कम होती है तो वह बाजार छोटे ऑर्डर आने पर कीमतों में बड़े बदलाव के लिए नाजुक हो जाता है। इससे बाजार में उठापटक की आशंका बढ़ती है। अनिश्चित माहौल में आर्थिक एजेंटों को गहरे एवं तरल बाजारों की उपलब्धता और आकलित कीमत में भरोसे की जरूरत होती है। ऐसी असामान्य स्थिति में तमाम वित्तीय आर्थिक सुधारों की जरूरत है जो बाजार में तरलता बढ़ा सकें।

7. मौद्रिक नीति को इस हिसाब से शिथिल किया गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति लक्ष्य चार फीसदी को हासिल किया जा सके। यह स्थिरता का एक स्रोत है। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) को मुद्रास्फीति पूर्वानुमान और चार फीसदी महंगाई के लक्ष्य को हासिल करने की राह पर ही बने रहना चाहिए। हालांकि अगले एक-दो महीनों में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है लेकिन मौद्रिक नीति एक-डेढ़ साल का दायरा लेकर चलती है लिहाजा थोड़े समय के आपूर्ति गतिरोधों को पार कर जाएगी। अगर सरकार एमपीसी और मुद्रास्फीति लक्ष्य के नियम-आधारित प्रारूप पर टिकी रहती है तो अनिश्चितता बढ़ेगी और फिर आम लोगों को मौद्रिक नीति पर भरोसा बहाल करने में एक दशक तक लग सकता है।

8. विनिमय दर का लचीला होना भी समायोजन के लिए जरूरी है। स्थानीय झटका होने पर बाजार विनिमय दर गिरती है और इससे व्यापारिक क्षेत्र प्रभावित होते हैं। परिपक्व बाजारों में वृहद-आर्थिक नीति से भारत के व्यापार-योग्य क्षेत्र पर सकारात्मक असर पड़ेगा, बशर्ते भारत विनिमय दर प्रबंधन से परहेज करे।

9. यह समय पूंजीगत नियंत्रणों को उदार बनाने और बाधाओं को हटाने के अनुकूल है ताकि वित्तीय एवं जन-हितैषी पूंजी का प्रवाह बढ़ाया जा सके। भारत में नजर आने वाले अवरोधों का विश्लेषण कर उन्हें दूर करने की जरूरत है। मसलन, आरबीआई और वित्त मंत्रालय के अलावा आयकर विभाग जैसी एजेंसियां भी पूंजी पर गहरा नियंत्रण रखती हैं। उदारीकरण का काम पूरे परिदृश्य के लिए किया जाना है। ऐसे उदारीकरण से पूंजीगत अवरोधों को दूर करने, नीतिगत प्रक्रिया में सुधार और कुछ प्रभावित लोगों की मदद की जा सकेगी।

10. राजकोषीय नीति क्या कर सकती है?

■ महामारी के दस्तक देने के पहले ही हमारा राजकोषीय घाटा काफी बढ़ा था। ऑटोमेटिक स्थिरांक के सक्रिय होने पर राजकोषीय घाटा अपने-आप बढ़ेगा। ऐसे में विवेकाधीन कदमों की गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि उनसे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा।

■ अपने संसाधनों को जन स्वास्थ्य में झोंकना राजकोषीय संसाधनों का बढ़िया उपयोग है। मसलन, प्रति व्यक्ति टेस्टिंग पर करीब 2,000 रुपये का खर्च आने और एक दिन में करीब पांच लाख लोगों का परीक्षण करने पर एक अरब रुपये प्रतिदिन की लागत आएगी।

■ नकदी अंतरण कार्यक्रमों का इस्तेमाल गरीब लोगों को पैसे भेजने के लिए किया जा सकता है।

■ उर्वरक सब्सिडी पर होने वाले व्यय में कटौती कर स्वास्थ्य एवं सब्सिडी व्यय की राजकोषीय गुंजाइश बनाई जा सकती है।

■ राज्य सरकारों के पास राजकोषीय गुंजाइश है क्योंकि वे राजकोषीय जवाबदेही नियमों के तहत तय सीमा के नीचे हैं

11. जीएसटी एवं पेट्रोलियम कीमतों के सुधारों को एक साथ जोड़ दिया जाए। कच्चे तेल के दाम 26 डॉलर प्रति बैरल होने से इसके लिए मौका भी अच्छा है।

■ सभी उत्पादों के लिए जीएसटी की एक निचली दर रखने की मांग बहुत पुरानी है।

■ पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें तय करने में सरकार की भूमिका सीमित करने की मांग पुरानी है।

■ मौजूदा समय में कमजोर तबकों तक सार्वजनिक पैसा पहुंचाने की तत्काल जरूरत है। इन परिवारों के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर होने वाला प्रत्यक्ष एवं परोक्ष व्यय उनके उपभोग का एक बड़ा अंश होता है।

■ पेट्रोलियम उत्पादों एवं कोयले को जीएसटी दायरे में लाने और जीएसटी की केवल एक दर तय कर देने से ये तीनों मकसद पूरे हो सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम एवं कोयले पर उत्पाद शुल्क की भी जरूरत है। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण में सरकारी भूमिका पर फौरन रोक लगाई जानी चाहिए।

■ इस कदम से सीमित अवधि में राजकोषीय घाटा बढ़ेगा लेकिन गरीब परिवारों के पास कुछ अधिक पैसे पहुंचेंगे। पेट्रोलियम कीमतें कम होने से ढुलाई पर निर्भर उत्पादों की कीमतें भी कम होंगी। यह लंबे समय से लंबित संरचनात्मक सुधार भी है जो भारत को एक परिपक्व बाजार बनाएगा। इससे निजी क्षेत्र का भरोसा बढ़ता है और वी-आकार वाली रिकवरी में मदद मिलती है।

अनुसंधान पर जोर

पूरी दुनिया परीक्षण, वैक्सीन, इलाज एवं दवाओं की तलाश में लगी है। दुनिया भर में सुरक्षात्मक पोशाक पीपीई और वेंटिलेटर की कमी देखी जा रही है। यह भारत की विनिर्माण इकाइयों के लिए नवाचार से जुड़ने और दुनिया की सेवा करने का बड़ा मौका है। भारत पहले भी वैक्सीनों के मामले में आगे रहा है। कोविड-19 परीक्षण में कुछ नवाचार निजी क्षेत्र के साथ काम कर रहे सीएसआईआर की कोशिशों का नतीजा हैं। राज्य के दिए बड़े करारों से अर्थव्यवस्था को बड़ा बल मिलता है। भारत में ऐसे बौद्धिक समुदाय की जरूरत है जो विज्ञान, बायो-मेडिकल इंजीनियरिंग, स्वास्थ्य नीति, वृहद-अर्थशास्त्र और वित्त में उपलब्ध वैश्विक ज्ञान को भारतीय जरूरतों के हिसाब से ढाल सके। इसके अलावा भारत के लिहाज से अहम इन सवालों के जवाब भी तलाशने होंगे।

1. कोरोनावायरस भारत की गर्मी, धूप और उमस वाले माहौल में किस तरह संचरित होता है?

2. बिल्ट परिवेश की क्या भूमिका है? अगर दरवाजे एवं खिड़कियां खुली थीं और हवा का प्रवाह बढ़ाने के लिए टेबल फैन लगाए गए तो इससे क्या कोई मदद मिलेगी?

3. भारत में मौजूद कोरोनावायरस की किस्म यहां की जेनेटिक प्रकृति और प्रतिरोधक क्षमता को देखते हुए कैसे काम करती है?

4. कुछ साक्ष्य हैं कि वायरस हवा में ठोस कणों के जरिये फैल सकता है। यह ठंड का मौसम आने पर उत्तर भारत में घातक संचरण कर सकता है। इस बारे में ठोस साक्ष्य तलाशने की जरूरत है ताकि सर्दियां आने पर उत्तर भारत में हवा की गुणवत्ता को बेहतर रखने पर जोर रहे।

5. भारतीय हालात में कोविड महामारी के मरीजों की स्वास्थ्य देखभाल के प्रोटोकॉल क्या हैं? महामारी से संबंधित जन स्वास्थ्य पहलुओं की लागत में बड़ी कटौती कैसे की जा सकती है?

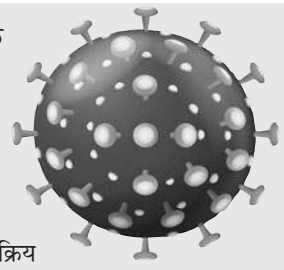

6. वैश्विक स्तर पर सक्रिय महामारी विशेषज्ञों के ज्ञान को भारतीय संदर्भ में देखा जाए। भारत के आंकड़ों की सटीकता के लिए सर्वे एवं पैनल आंकड़ों को किस तरह आंका जाए?

7. महामारी अधिनियम, 1897 की जगह नई व्यवस्था कैसे की जाए जो आधुनिक भारत के संविधानवाद में यकीन रखने के साथ नियंत्रण एवं संतुलन भी रखता हो?

8. शिनाख्त-परीक्षण-अलगाव-इलाज का पुराना भारतीय तरीका क्यों कारगर नहीं है? इन सभी अवयवों के बेहतर प्रदर्शन के लिए किन संस्थागत बदलावों की जरूरत है?

9. स्वास्थ्य देखभाल की जरूरत अचानक बढ़ने पर स्वास्थ्य नीति में कैसे तेजी लाई जाए?

10. सरकार निजी क्षेत्र को जोड़ने के करारों से संबंधित सार्वजनिक वित्त प्रबंधन की समस्याओं से कैसे निपट सकती है? इसके लिए खरीद, अनुबंध प्रबंधन एवं भुगतान की संशोधित प्रणाली की जरूरत होगी।

11. अगले दो साल- 2020 और 2021 में वृहद-आर्थिक एवं वित्तीय नीति को क्या करना चाहिए?

भारतीय शोध जगत और इसके लोक-हितैषी फंडिंग स्रोतों को इन सवालों के जवाब तलाशने होंगे क्योंकि भारत के लिहाज से ये काफी अहम हैं पर इन्हें कम अहमियत दी जाती है।

निष्कर्ष

कोविड-19 महामारी एक त्रासदी है लेकिन हम पर निर्भर करता है कि यह प्रलय न बने। भारतीय राज्य की कमजोर क्षमता ही हमारी सबसे अच्छी राह को आकार और सीमित करती है। हमें विकसित देशों के नीतिगत कदमों की बराबरी का दबाव नहीं महसूस करना चाहिए। उनके सबसे सही एवं समझदारी भरे कदम अक्सर हमारे लिए गलत होते हैं। अमेरिका अपने नागरिकों को चेक भेज रहा है तो यह मतलब नहीं है कि भारत भी हरेक नागरिक को 3,000 रुपये भेजने लगे। हमें भारतीय परिस्थितियों और क्षमता को ध्यान में रखने के साथ ही ताकत के इस्तेमाल में भी सावधानी रखनी होगी। अगर हम सार्वजनिक वित्त के सिद्धांतों पर न चले तो हमारी समस्या और बढ़ जाएगी। कम सरकारी क्षमता एवं कम जानकारी होने और अपने जटिल सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में कम समझ होने पर कई बार सबसे अच्छा तरीका उत्तम निष्क्रियता का होता है। हमें तात्कालिक जरूरतों से परे मध्यम अवधि का नजरिया रखना चाहिए। कुछ महीनों में महामारी के चलते रोजाना होने वाली मौतें कम होने लगेंगी। यह कोई जंग नहीं है, हम अपने भौतिक एवं संस्थागत ढांचे को बरकरार रखते हुए उबर जाएंगे। अर्थव्यवस्था की वी-आकार वाली रिकवरी के लिए स्वास्थ्य, वृहद-आर्थिक एवं वित्तीय नीति पर ध्यान देना होगा। इसके लिए अगले दो साल तक सूझबूझ भरे फैसलों की दरकार है। इसी से निजी निवेश में अपेक्षित बढ़त हो सकेगी।

(लेखक एनआईपीएफपी के क्रमशः चेयरमैन एवं प्रोफेसर हैं)

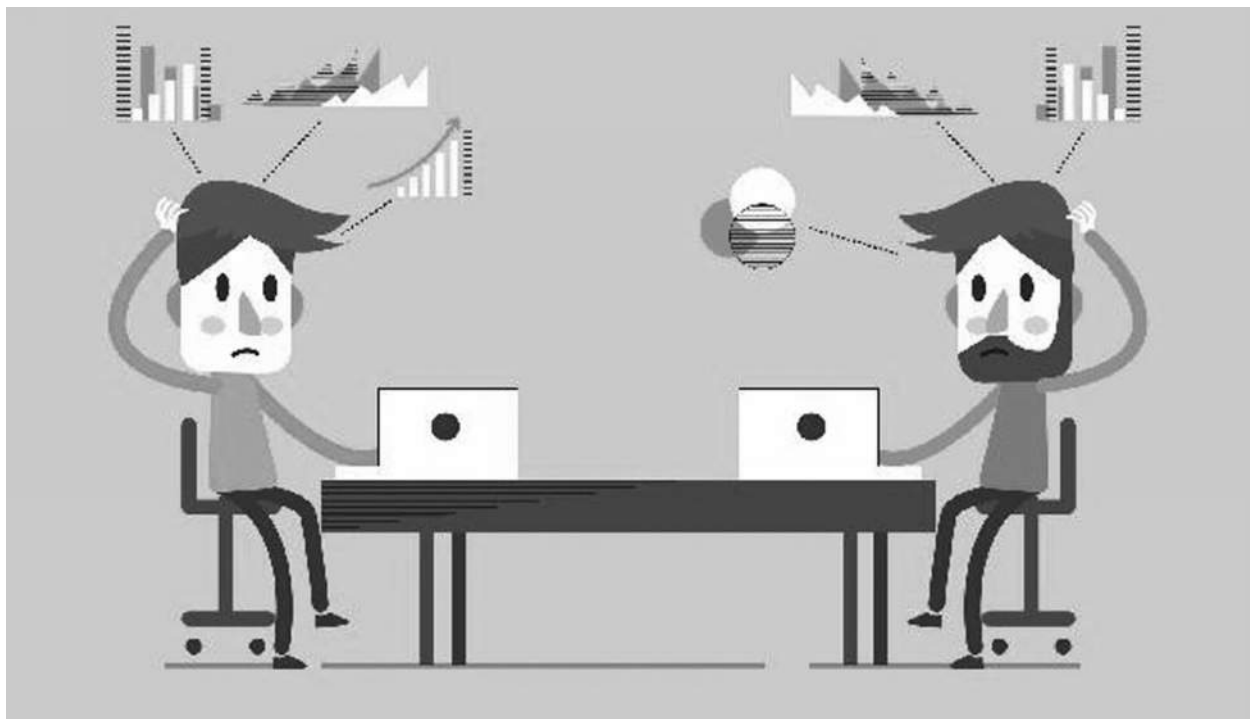

लॉकडाउन की आफत में दुरुस्त रखें घर का बजट

एक-एक रुपया सोच-समझकर इस्तेमाल करें, पाई-पाई बचाएं, फिजूलखर्ची से एकदम दूर रहें और याद रखें कि यह मुश्किल दौर भी गुजर जाएगा

बिंदिशा सारंग

चीन से निकले कोरोनावायरस के बारे में सोचना बहुत हो गया। अब वक्त है उन सवालों के व्यावहाारिक जवाब का, जो इसके कारण हमारे दैनिक जीवन में आए हैं। मुंबई के प्रमाणित वित्तीय योजनाकार पंकज मठपाल ने कहा, 'हम सभी को अलग-थलग रहना होगा और महीनों घर से काम करना होगा। शायद देर-सबेरे कम वेतन पर काम करना होगा या बिना वेतन के हालात से भी जूझना होगा। इस तरह हरेक व्यक्ति को नए माहौल से पार पाने के लिए अपनी वित्तीय रणनीतियों में बदलाव लाने की जरूरत है।'

उन्होंने कहा, 'इसका मतलब है कि अपने नकदी प्रवाह (पैसे की आमदनी एवं खर्च) का ठीक से ध्यान रखा जाना चाहिए और उनमें हालात के मुताबिक बदलाव किया जाना चाहिए।' संक्षेप में कहें तो अगर आपने पहले से ही घरेलू मासिक बजट बनाया हुआ है तो आपको इसमें सुधार करना होगा। अगर घरेलू बजट नहीं बनाया हुआ है तो अब ऐसा करने का वक्त आ गया है।

बजट बनाने के 10 कदम

पहला
तीन मानसिक स्थितियां बनाएं (सबसे बुरी, सामान्य और बेहतर)

दूसरा
अपनी संभावित नई आमदनी का अनुमान लगाएं

तीसरा
अपने मौजूदा निश्चित और परिवर्तनशील खर्चों को समझें

चौथा
विश्लेषण करें और परिवर्तनशील खर्च कम करें

पांचवां
हर एक रुपये का सोच-समझकर इस्तेमाल करें

छठा
अगर कोई आपात कोष नहीं है तो लिक्विड फंड या बचत खाते के जरिये आपात कोष बनाना शुरू करें

सातवां
ऋणों को सस्ती ब्याज दरों वाले बैंकों में ट्रांसफर करें

आठवां
खुद और अपने परिवार के लिए व्यक्तिगत चिकित्सा बीमा खरीदें या बढ़ाएं

नवां
अगर आपात कोष है तो यथासंभव निवेश जारी रखें

दसवां
भ्रमित हैं तो प्रमाणित वित्तीय योजनाकार से पेशेवर सलाह लें

वित्तीय स्थिति का आकलन

सबसे पहले अपनी वित्तीय स्थिति का जायजा लें। अपनी आमदनी, खर्च, परिसंपत्तियों, बीमा कवर आदि को जानें। एनए शाह एसोसिएट्स में संस्थापक साझेदार चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक शाह ने कहा, 'अपने बजट का फिर से आकलन करते वक्त आपको सबसे बुरे, सामान्य और अच्छे हालात के बारे में सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि उन हालात में आप क्या करेंगे।'

सबसे बुरे हालात यह हो सकते हैं कि आपकी नौकरी चली जाए या वेतन में 20 से 30 फीसदी की बड़ी कटौती हो जाए। सामान्य हालात वे हैं, जिनमें आम तौर पर स्थितियां वित्तीय रूप से बहुत ज्यादा नहीं बदलती हैं या केवल मामूली बदलती हैं। बेहतर हालात वे हो सकते हैं, जिनमें आपकी आमदनी पर कोई असर न पड़े और लॉकडाउन एवं घर से काम करने की वजह से आपकी जेब में ज्यादा पैसा आए। शाह कहते हैं, 'हर हालात के हिसाब से अपने नकदी प्रवाह का अनुमान लगाएं। यह पता करें कि प्रत्येक स्थिति में आप कितने महीने टिके रह सकते हैं। अगर आप अगले महीने बीमार पड़ जाते हैं तो आप इस खर्च को तीन साल बाद के लिए नहीं टाल सकते। आपको इसके लिए पैसा खर्च करना होगा। अगर आपके लिए हालात बदलते हैं तो परिसंपत्तियों की बिक्री की रणनीति बनाने से आप उन्हें औने-पौने दाम पर बेचने से बच जाएंगे।' यह वह समय है, जब आप अपने दिमाग में रणनीति के खाके बना लें, खर्च का फिर से आकलन और आवंटन करें, परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त आमदनी का आकलन करें और आपात योजना बनाएं।

खर्च

आपकी स्थिति कितनी ही अच्छी क्यों नहीं हो, आपको अपने खर्चों में और कटौती करनी ही चाहिए। लॉकडाउन के कारण कुछ खर्च तो अपने आप ही बंद हो गए हैं जैसे फिल्म देखने बाहर जाना, रेस्तरां में खाना या कपड़े खरीदना। मठपाल ने कहा, 'घर पर होने के बावजूद हम कुछ गैर जरूरी खर्चों को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। जिन लोगों के पास एमेजॉन प्राइम की सेवा पहले से ही है मगर वे नेटफ्लिक्स का कनेक्शन भी ले रहे हैं या यूट्यूब से फिल्में खरीद रहे हैं, वे असल में घर बैठे ही अपने खर्चों में इजाफा करते जा रहे हैं।'

याद रखें कि खर्च दो तरह के होते हैं- तय और परिवर्तनशील। परिवर्तनशील श्रेणी को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है-आवश्यक और स्वैच्छिक। आवश्यक परिवर्तनशील खर्च वे होते हैं, जिनके बिना आप जीवन नहीं जी सकते। उदाहरण के लिए किराना, बिजली बिल, मोबाइल बिल और अन्य जरूरतें। लेकिन स्वैच्छिक खर्च मसलन ऑनलाइन मनोरंजन आदि में आप कमी कर सकते हैं क्योंकि इन दिनों मनोरंजन के लिए बहुत से मुफ्त संसाधन उपलब्ध हैं।

नकदी

इसके बाद देखिए कि आपके हाथ में कितना पैसा है। मठपाल ने कहा, 'इस समय नकदी रखना सबसे जरूरी है। अगर आपके पास छह महीने घर चलाने का पैसा जमा है तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। जिनके पास ऐसा कोष नहीं है, उन्हें दफ्तर आने-जाने में रोज होने वाला खर्च एक जगह इकट्ठा कर लेना चाहिए। यह रकम बहुत ज्यादा नहीं होगी मगर शुरुआत तो होगी और इस समय यही सबसे अच्छी शुरुआत होगी।'

कुबेर डॉट इन के मुख्य कार्याधिकारी गौरव रस्तोगी ने कहा, 'अगर आपके पास आपात कोष नहीं है तो आप आगे जो राशि बचा सकते हैं, उसे लिक्विड फंडों में लगाएं। कुल मिलाकर आपात कोष में इतनी राशि रखी जानी चाहिए, जो यह मुश्किल दौर खत्म होने तक पर्याप्त हो। विशेषज्ञ कम से कम छह महीने के खर्च लायक राशि आपात कोष में रखने की सलाह देते हैं।'

कर्ज

बैंक बहुत से ऋणों पर तीन महीने ईएमआई टाल रहे हैं। अगर आप किस्त चुकाने में सक्षम हैं तो इस मोहलत से बचें। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है और आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। पैसा बचाने का एक अन्य तरीका ब्याज की लागत को कम करना है। माना कि आपने पिछले साल नवंबर में ऊंची दर पर पर्सनल लोन लिया था और अब पर्सनल लोन की दरें घट गई हैं। ऐसे में आप इस कर्ज को उस ऋणदाता के पास ट्रांसफर करा सकते हैं, जो सस्ता कर्ज दे रहा है। निस्संदेह आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसमें बचत काफी अधिक है और नए कर्ज की प्रोसेसिंग फीस बहुत अधिक नहीं है।

निवेश

अगर आपके वेतन में कटौती होती है तो आप आगे शायद पहले जितनी राशि का निवेश नहीं कर पाएं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आपको निवेश बंद करने की जरूरत है, विशेष रूप से उस स्थिति में जब आपके पास आपात कोष है। रस्तोगी कहते हैं, 'मौजूदा लॉकडाउन जैसे समय में बहुत से लोगों का खर्च पहले के महीनों की तुलना में 30 से 40 फीसदी कम हो चुका है। हमें नहीं लगता कि अगले छह महीनों में ज्यादातर लोगों के वेतन में 10 से 15 फीसदी से अधिक कमी आएगी। दुनिया भर के अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अगले छह महीनों के दौरान भारत समेत पूरे विश्व में निजी कंपनियों की बचत में भारी बढ़ोतरी होगी।'

इसका मतलब है कि आपका खर्च आपकी आमदनी से ज्यादा घट सकता है। रस्तोगी ने कहा, 'जब बजट बनाने की बात आती है तो आपको अगले छह महीने में अपनी आमदनी में संभावित कमी का आकलन करने की जरूरत है। अगर आपके वेतन में कटौती नहीं होती है और आपके खर्चों में कमी आती है तो आपकी बचत बढ़ेगी, जिसे आपको निवेश करना चाहिए। अगर आप इक्विटी में निवेश का जोखिम नहीं उठा सकते तो आपको कम जोखिम वाले निवेश करने चाहिए।' मठपाल ने जोखिम कम करने के बारे में कहा, 'अगर आपका नियोक्ता चिकित्सा बीमा मुहैया कराता भी है तो आपको जल्द से जल्द अपने और अपने परिवार के लिए व्यक्तिगत बीमा खरीदना चाहिए। मौजूदा अर्थव्यवस्था में बहुत से लोगों की नौकरी जाने की आशंका है।'

सच्चाई यह है कि आपको अपना नया बजट बनाने पर काम करना होगा, ये केवल कुछ दिशानिर्देश हैं। हर एक रुपये का सोच-समझकर इस्तेमाल करें। हरसंभव बचत करें। इसका नेटफ्लिक्स के बजाय स्वास्थ्य बीमा लेने में इस्तेमाल करें। यह मुश्किल दौर बीत जाएगा। शाह कहते हैं, 'इस समय मितव्ययी बनकर जिएं ताकि बाद में लंबे समय तक आराम से जी सकें।'

संकट बढ़ेगा तो सोने, चांदी का भाव चढ़ेगा

पुनीत वाधवा

पिछले एक साल में सोने के दाम पहले ही करीब 25 फीसदी चढ़ चुके हैं। विश्लेषकों का अनुमान है कि कोरोनावायरस (कोविड-19) के फैलने से इस पीली धातु की कीमतें लंबी अवधि में और चढ़ सकती हैं। हालांकि उनका अनुमान है कि निकट भविष्य में (छह महीने) में तेजी सीमित रहेगी क्योंकि पिछले एक साल में कीमतें काफी चढ़ चुकी हैं। सोने की कीमतें जनवरी 2019 में 1,321 डॉलर प्रति औंस के आसपास थीं, जो पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में 1,650 डॉलर प्रति औंस का स्तर पार कर सात साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी हैं। अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजार में इसका भाव 1,700 डॉलर प्रति औंस को भी लांघ चुका है।

मोतीलाल ओसवाल फाइनैंशियल सर्विसेज के सहायक निदेशक (जिंस अनुसंधान) किशोर नार्ने ने कहा, 'कोरोनावायरस से वैश्विक चिंताएं और बढ़ रही हैं। जब हम व्यापार युद्धों का समाधान निकलने की उम्मीद लगा रहे थे तब कोरोनावायरस ने सुस्त वैश्विक अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका दिया है।'

इस बीच कोरोनावायरस के संक्रमण के केंद्र चीन में इस बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या 2,700 से अधिक हो गई है। इसके अलावा वहां इस बीमारी के संक्रमण के पुष्ट मामले 78,400 से आगे निकल चुके हैं। मूडीज ने अनुमान जताया है कि अगर यह बीमारी महामारी में तब्दील हुई तो वैश्विक मंदी आएगी। वहीं ऐसा होने की बहुत अधिक आशंका है क्योंकि इस बीमारी का संक्रमण इटली और कोरिया में तेजी से फैल रहा है।

इक्विनॉमिक्स रिसर्च के संस्थापक और प्रबंध निदेशक जी चोकालिंगम ने कहा, 'सोने की कीमतों में पिछले एक साल के दौरान आई तेजी को देखते हुए इसमें अगले छह महीनों में सीमित बढ़ोतरी के आसार हैं। हालांकि यह देखना होगा कि कोरोनावायरस की स्थिति कैसी रहती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था कैसा प्रदर्शन करती है। कोरोनावायरस के मामलों या मौतों में बढ़ोतरी से निवेशकों का सोने और चांदी जैसी सुरक्षित परिसंपत्तियों की तरफ रुझान बढ़ेगा, जिससे इन कीमती धातुओं की कीमतें अभी और बढ़ेंगी।'

कोरोना का असर

- सोने के दाम जनवरी 2019 में 1,321 डॉलर प्रति औंस के आसपास थे
- अब 1,650 डॉलर का भाव पार कर ये सात साल के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं
- मूडीज ने अनुमान जताया है कि अगर कोरोनावायरस संक्रमण महामारी में तब्दील हुआ तो वैश्विक मंदी आएगी

> कोरोनावायरस के मामलों या मौतों में बढ़ोतरी से निवेशकों का सोने और चांदी जैसी सुरक्षित परिसंपत्तियों की तरफ रुझान बढ़ेगा

नीतिगत स्तर पर देखें तो वैश्विक केंद्रीय बैंकों के वृद्धि को सुधारने के लिए दरों में कटौती या अर्थव्यवस्था में ज्यादा नकदी झोंकने के रूप में ज्यादा प्रोत्साहन उपायों को अपनाने की संभावना है। इन कदमों से सोने सहित सभी परिसंपत्ति वर्गों में तेजी आ सकती है। विश्लेषकों ने कहा कि इस कदम को लेकर शेयर बाजार की कैसी प्रतिक्रिया रहेगी, यह कंपनियों की आमदनी पर निर्भर करेगा।

यूबीएस का अनुमान है कि वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर भारी चोट पड़ेगी। यह जनवरी 2020 की पहली तिमाही में घटकर 0.7 फीसदी पर आ सकती है, जो 2019 की चौथी तिमाही में 3.2 फीसदी थी। हालांकि इस ब्रोकरेज का अनुमान है कि अप्रैल-जून 2020 तिमाही में वृद्धि फिर सुधरेगी। हालांकि यह असर पूरे वर्ष 2020 में जीडीपी की वृद्धि को 20 आधार अंक घटाकर 2.9 फीसदी पर ला सकता है।

मॉर्गन स्टैनली में अर्थशास्त्री देयी तान ने हाल में एक रिपोर्ट में लिखा, 'अमेरिका और चीन के बीच कारोबारी तनाव से पहले ही जापान को छोड़कर पूरे एशिया में मौद्रिक नीति दरें वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे निचले स्तर पर आ गईं। कोरोनावायरस के कारण जापान को छोड़कर पूरे एशिया में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद सबसे ऊंचे स्तर की तरफ बढ़ रहा है। राजकोषीय और मौद्रिक नरमी के प्रयास तो किए जा रहे हैं। जापान को छोड़कर पूरे एशिया में राजकोषीय घाटा बढ़कर जीडीपी का 8.4 फीसदी होने का अनुमान है, जो 2019 में 7.8 फीसदी था।'

कोरोनावायरस के नाम पर लुटेरे लग गए काम पर

फिशिंग करने वाले कई गिरोह इस महामारी का फायदा उठाकर मैलवेयर फैला रहे हैं, गोपनीय जानकारी चुरा रहे हैं

बिंदिशा सारंग

इस समय पूरी दुनिया एक ही नाम जप रही है - कोविड-19। कोरोनावायरस की इस महामारी पर काबू करना और उसे खत्म करना ही इस वक्त सबकी सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन अफरातफरी के इस माहौल में भी एक पूरी जमात कुछ और ही साजिश रच रही है। इस माहौल का फायदा उठाकर वे धोखाधड़ी और जालसाजी में जुट गए हैं। इनका गोरखधंधा किसी भी रूप में सामने आ सकता है। ये कोरोनावायरस से लड़ने के लिए दान देने वालों को 'पीएम केयर्स' की फर्जी लिंक भेज सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार कर्ज की मासिक किस्त पर लगने वाली रोक के नाम पर आपको ठग सकते हैं और आपके करीब रहने वाले कोरोना पीड़ितों की जानकारी देने वाले किसी ऐप्लिकेशन में मैलवेयर भी भेज सकते हैं।

कोरोनावायरस का खौफ इस कदर पसरा हुआ है कि लोग आसानी से इस तरह की धोखाधड़ी के शिकार भी बन जा रहे हैं। मसलन 46 साल के उस शख्स को ही ले लीजिए, जो पड़ोस में रह रहे कोरोना मरीजों की एकदम सटीक जानकारी देने वाला ऐप डाउनलोड करने के चक्कर में 1 लाख रुपये से हाथ धो बैठा। बैराकुडा नेटवर्क्स में भारत के कंट्री मैनेजर मुरली उर्स कहते हैं, 'दुनिया का ज्यादातर हिस्सा कोविड-19 से जूझ रहा है और उस पर काबू करने की कोशिशों में जुटा हैं ऐसे में ईमेल और वेब पर इसके बारे में चर्चा जोरों पर है, जिसका फायदा साइबर हमलावर उठा रहे हैं।'

मोबाइल ऐप

इस समय कोरोनावायरस से जुड़े ऐसे कई ऐप हैं, जो वास्तव में मैलवेयर के जरिये धोखाधड़ी करते हैं। ये ऐप इस्तेमाल से पहले आपसे कई प्रकार की परमिशन यानी अनुमति मांगते हैं और आपको पता लगे बगैर ही मैलवेयर आपके मोबाइल फोन में पहुंच जाते हैं। क्लाउडकनेक्ट कम्युनिकेशंस के सह-संस्थापक और मुख्य कार्य अधिकारी रमन सिंह समझाते हैं, 'दूरसंचार विभाग ने हाल ही में कोविड-19 की बात करने वाली ऐसी वेबसाइट की सूची जारी की, जो बेहद खतरनाक हैं। इनमें संक्रमित यूजर्स के फर्जी नक्शे जैसी तमाम सामग्री दिखाई जाती है। फर्जी नक्शे तैयार करने के लिए ये यूजर से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का अनुरोध करते हैं और उनकी सुरक्षा में सेंध लगाते हैं।' मोटे तौर पर समझ लीजिए कि आप जो भी डाउनलोड करते हैं, उसमें सावधानी बरतें और इस बात का खास ध्यान रखें कि आप किस तरह की परमिशन उस ऐप को दे रहे हैं।

कैसे बचें

पूछिए कि हीट-मैप यानी संक्रमित व्यक्तियों का नक्शा मुहैया कराने के लिए ऐप को मेरे एसएमएस पढ़ने की क्या जरूरत है या उसे मेरे मोबाइल से कॉल रिकॉर्ड करने या कॉल करने की क्या जरूरत आन पड़ेगी।

दान, इलाज की आड़ में घोटाले

उर्स कहते हैं, 'घोटालेबाज कोरोनोवायरस के इलाज या फेस मास्क बनाने वाली कंपनियों में निवेश करने के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। कोरोनावायरस के टीके विकसित करने के नाम पर फर्जी कंपनियां बनाई गई हैं। इसी तरह, दान के नाम पर कई तरह के फर्जी खाते या फिशिंग जैसे मामले भी सामने आए हैं।'

कैसे बचें

इस तरह के ईमेल न खोलें। अगर मैसेज आया है तो उसमें दी गई लिंक पर क्लिक न करें। साथ ही किसी विश्वसनीय संस्थान की वास्तविक वेबसाइट पर जाकर ही दान दें।

ईएमआई धोखाधड़ी

इस तरह के मामलों में धोखाधड़ी करने वाले आपसे संपर्क करते हैं और ईएमआई रोकने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ओटीपी मांगते हैं। पैसाबाजारडॉटकॉम के सह-संस्थापक तथा मुख्य कार्याधिकारी नवीन कुकरेजा कहते हैं, 'ईएमआई पर अगले तीन महीने की रोक लगाने या इसे स्वीकार नहीं करने के लिए ओटीपी साझा करने की आवश्यकता नहीं है।' कर्ज देने वाला बैंक आपसे संपर्क करेगा, लेकिन इसके लिए ओटीपी की मांग कभी नहीं की जाएगी।

कैसे बचें

यदि बैंक कर्मी आपसे ओटीपी मांग रहा है तो समझ जाइए कि वह कर्मचारी नहीं धोखेबाज है।

ईमेल पर धोखाधड़ी

धोखेबाजों के लिए यह आप तक पहुंचने का सबसे बेहतर रास्ता है क्योंकि ईमेल से जुड़ा ब्योरा डार्कनेट पर आसानी से उपलब्ध है। क्विक हील सिक्योरिटी लैब्स के निदेशक हिमांशु दुबे कहते हैं, 'इनमें से कई मेल विश्व स्वास्थ्य संगठन से जुड़े होने का दावा करते हैं। इन्हें काफी अच्छे तरह से लिखा जाता है और ये डब्ल्यूएचओ के दिशानिर्देशों को आप तक पहुंचाने का दावा करते हैं।' इसमें जालसाज आपको संबंधित फाइल खोलने के लिए झांसा देता है। वह आगाह करते हैं, 'जैसे ही आप मेल से जुड़ी फाइल खोलेंगे वैसे ही कंप्यूटर पर मालवेयर डाउनलोड हो जाएगा, जो लॉगइन या ब्राउजर के इतिहास से जुड़ी जानकारी चुरा लेगा। बड़ा जोखिम यह है कि इसके जरिये आपकी वित्तीय जानकारी भी चोरी की जा सकती है।'

उर्स कहते हैं, 'अगर आपके पास आमतौर पर किसी संस्था से मेल नहीं आती हैं तो अब आने वाली ईमेल के दावों की पुष्टि जरूर करें।' इस तरह के फिशिंग ईमेल के जरिये आपकी जानी पहचानी वेबसाइट को खोलने के लिए ही कहा जाता है लेकिन मेल में दी गई लिंक फर्जी साइट पर ले जाती है और दर्ज होने वाले आंकड़े जुटा लेती है।

कैसे बचें

लैपटॉप या मोबाइल में किसी वेबसाइट के पासवर्ड को कभी सहेजकर यानी सेव करके नहीं रखों क्योंकि सेव की गई जानकारी चुराना मालवेयर के लिए बहुत आसान होता है। मेल या मैसेज में दी गई लिंक खोलने के बजाय अलग से ब्राउजर में अपने बैंक खाते की लिंक स्वयं लिखकर ही खोलें और जांच के बाद ही आगे बढ़ें।

नई दिल्ली | 11 अप्रैल 2020 शनिवार बिज़नेस स्टैंडर्ड

कोरोना की जांच में तेजी की तैयारी

माना जा रहा है कि अपने घरों तक सीमित संदिग्धों में लक्षण दिखने शुरू हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर जांच से उनकी पहचान करके उन्हें अलग करना ही एकमात्र तरीका है

बीएस संवाददाता

देश में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का तीसरे हफ्ता चल रहा है और राज्य अपनी जांच क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। माना जा रहा है कि अपने घरों तक सीमित संदिग्धों में लक्षण दिखने शुरू हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर जांच से उनकी पहचान करके उन्हें अलग करना ही एकमात्र तरीका है। देश के महानगरों में कई स्थानों पर यह महामारी विकराल रूप ले रही है और इसके मद्देनजर देश की सर्वोच्च शोध संस्था भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए इन स्थानों पर त्वरित स्क्रीनिंग टेस्ट (खून के नमूनों के इस्तेमाल से) की प्रकिया तेज करने की सलाह दी है।

अधिकांश राज्यों में रोजाना 600 से 1,500 लोगों की जांच की जा रही है और वे 50,000 से 100,000 जांच किट का ऑर्डर दे चुके हैं। केंद्र के स्तर पर करीब 7,00,000 टेस्ट किट 10 अप्रैल के आसपास पहुंचने की उम्मीद है और तब तक व्यापक पैमाने पर जांच को इंतजार करना पड़ेगा। त्वरित जांच में खून के नमूने लिए जाते हैं। इसमें ऐसे एंटीबॉडीज का पता लगाया जाता है जो कोरोनावायरस प्रोटीन पर प्रतिक्रिया देती हैं और इसमें कुछ ही मिनटों के भीतर नतीजे आ जाते हैं। इसके बाद पंरपरागत पॉलिमीरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) जांच होगी जिसमें नतीजे आने में कुछ घंटों का समय लगता है।

लेकिन जांच किट की उपलब्धता चिंता का विषय हैं। साथ ही देश में संक्रमण से बचने के लिए स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा पहने जाने वाले उपकरण पीपीई की भी कमी है। भारत में रोजाना करीब 20,000 नमूनों की जांच हो रही है और अगले कुछ हफ्तों में इसे 100,000 तक पहुंचाने की योजना है। एक जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ का कहना है कि देश में कोरोनावायरस के सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए कम से कम 13 करोड़ लोगों की जांच की जरूरत है जो कि देश की कुल आबादी का महज 10 फीसदी है। इस समय तो यह बेहद मुश्किल लक्ष्य लगता है।

महाराष्ट्र ने बुधवार को कहा कि उसके पास पीपीई किट की कमी हो रही है और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) हर हफ्ते 35,000 पीपीई किट खरीदने की योजना बना रही है। अब तक करीब 12,000 पीपीई विमान द्वारा लाए गए हैं और करीब 30,000 रास्ते में हैं। बीएमसी ने भी 50,000 त्वरित जांच किट का ऑर्डर दिया है। बीएमसी का कहना है कि शहर में कोरोनावायरस सामुदायिक प्रसार के चरण में पहुंच चुका हैं क्योंकि जो नए मामले आ रहे हैं, उनका न तो मरीजों से कोई संपर्क रहा है और न ही उन्होंने कोई विदेश यात्रा की है। मुंबई में वर्ली, प्रभादेवी और लोअर परेल के अलावा धारावी सबसे प्रभावित इलाके हैं।

राज्यों में रोजाना 600 से 1,500 लोगों की जांच हो रही है। वे 50 हजार से एक लाख जांच किट का दे चुके हैं ऑर्डर

शहर में 50 से अधिक स्वास्थ्यकर्मियों में कोविड-19 के पॉजिटिव मामले पाए गए हैं। मुंबई में प्रति दस लाख लोगों पर 890 लोगों की जांच हो रही है। बीएमसी का दावा है कि यह औसत दिल्ली से बेहतर है जहां प्रति दस लाख लोगों में केवल 96 लोगों की जांच हो रही है। निजी लैबों को रोजाना 25 जांच मुफ्त करने को कहा गया है।

दिल्ली सरकार ने 100,000 त्वरित जांच किट का ऑर्डर दिया है और उसे हाल में आईसीएमआर से इस तरह के कई किट मिले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सबसे अधिक प्रभावित 15 जिलों को सील कर दिया है और रोज 1,500 संदिग्धों की जांच की तैयारी में जुटी है। राज्य सरकार की गुरुवार से रोज दोगुना जांच करने की योजना है। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बुधवार को कहा कि राज्य में कोविड-19 से प्रभावित जिलों के अलावा बाकी जिलों में भी संदिग्धों की जांच की जाएगी ताकि इसके प्रसार को कम से कम किया जा सके। साथ ही ऐसे लोगों के नमूने भी लिए जाएंगे जिनमें सांस की बीमारी या इनफ्लूएंजा के लक्षण हैं। त्वरित जांच किट की खरीद के लिए निविदा 11 अप्रैल को खोली जाएगी। प्रसाद ने कहा, ये एंटीबॉडी जांच किट स्वास्थ्यकर्मियों और क्वारनटीन केंद्रों में इस्तेमाल किए जाएंगे क्योंकि राज्य में कोरोनावायरस के मामलों में अब स्थिरता आ रही है। अब बड़े पैमाने पर जांच कराने का समय आ गया है ताकि पॉजिटिव मामलों की संभावना को खत्म किया जा सके। राज्य सरकार आने वाले दिनों में 24 जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जांच की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रही है। अभी केवल 10 जिला अस्पतालों में ही यह सुविधा है। इसके अलावा राज्य के सभी 75 जिलों में कोरोनावायरस के नमूने एकत्र करने के लिए केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

दक्षिणी राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने नमूने एकत्र करने के लिए कियोस्क की व्यवस्था अपनाई है। तमिलनाडु ने चीन से 100,000 त्वरित जांच किट मंगाए हैं जिनके 9 अप्रैल को पहुंचने की उम्मीद है। इनसे जांच की शुरुआत 10 अप्रैल के आसपास होगी। तमिलनाडु के पास 7 अप्रैल तक करीब 14,000 जांच किट थे जो उसे पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान से मिले थे। राज्य में बुधवार तक 6,000 से अधिक लोगों की जांच की है। राज्य में अभी 19 जांच केंद्र हैं जिनकी संख्या बढ़ाकर दोगुना की जा रही है। दक्षिण कोरिया की तर्ज पर तिरुपुर के सरकारी अस्पताल में वॉक-इन सैंपल कियोस्क स्थापित किया गया है। इन स्टेराइल कैबिन में बाहर खड़े मरीजों के गले से नमूने लिए जा सकते हैं। इससे कम समय में ज्यादा नमूने एकत्र किए जा सकते हैं। इसमें पीपीई किट की भी जरूरत नहीं है।

केरल के एर्णाकुलम में भी इसी तरह की व्यवस्था की गई है। केरल को पुणे की माईलैब से 1,000 पीसीआर जांच किट की पहली खेप मिल चुकी है। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने इनका ऑर्डर दिया था। अब राज्य को त्वरित जांच किट का इंतजार है। केरल चीन से 100,000 ऐसे किट खरीद रहा है। इनमें से 25,000 किट आने में देरी हुई है क्योंकि चीन में जहाजों को हरी झंडी नहीं मिली। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का कहना है कि राज्य में जांच किट की कोई कमी नहीं है। राज्य को गुरुवार को आईसीएमआर से 20,000 किट मिलेंगे।

कर्नाटक भी सिंगापुर की एक कंपनी से 100,000 एंटीबॉडी किट खरीदने की प्रक्रिया में है और उसकी योजना जांच की संख्या बढ़ाने की है। राज्य में अभी रोजाना 600 से 800 लोगों की जांच हो रही है। राज्य में चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर को कोविड-19 से जुड़े सभी मामलों का प्रभारी बनाया गया है। उनका कहना है कि इन जांच किट का इस्तेमाल सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में किया जाएगा। साथ ही सामुदायिक प्रसार रोकने के लिए कुछ लोगों की औचक जांच भी की जाएगी। कर्नाटक भी स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए दस लाख पीपीई किट खरीदने की प्रक्रिया में है।

आंध्र ने भी 100,000 त्वरित एंटीबॉडी जांच किट का ऑर्डर दिया है ताकि ज्यादा जोखिम वाले वर्गों की जांच की जा सके। उसने जांच क्षमता में विस्तार किया है और अब रोजाना 5,000 से 6,000 नमूनों की जांच की जा रही है। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों, स्वास्थ्यकर्मियों और ज्यादा जोखिम वाले मरीजों में लक्षणों का पता लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रोज इन वर्गों के 1,800 से 2,000 नमूनों की जांच की योजना है। इसके अलावा ऐसे इलाकों से करीब 1,000 लोगों के खून के नमूने लिए गए हैं जहां कोरोनावायरस के मरीज मिले हैं। कोरोनावायरस के संभावित संक्रमण से निपटने के लिए विभाग के पास हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की 20 लाख और एजिथ्रोमाइसिन की 14 लाख गोलियों का भंडार है। राज्य सरकार कोरोनावायरस से प्रभावित मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्यकर्मियों के लिए पहले ही 20 लाख पीपीई और 14 लाख एन-95 मास्क के ऑर्डर दे चुकी है। आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन ने रोजाना 2,000 टेस्टिंग किट बनाना शुरू तक दिया है। इस क्षमता को बढ़कर 25,000 किया जाएगा।

हालांकि तेलंगाना सरकार ने अलग रास्ता चुना है। उसने दूसरे राज्यों के उलट त्वरित जांच नहीं करने का फैसला किया है। उसका कहना है कि संक्रमण के मामलों की पुष्टि के लिए परंपरागत जांच ही जरूरी है। राज्य सरकार ने करीब 200,000 परंपरागत जांच किट, 500,000 पीपीई, 500,000 एन-95 मास्क, 25 लाख नियमित मास्क और 25 लाख सर्जिकल दस्ताने मंगाए हैं। सरकार कोरोनावायरस के मामलों से निपटने के लिए अस्पतालों को रोजाना 5,000 से 10,000 पीपीई वितरित कर रही है।

गुजरात ने आईसीएमआर से 50,000 अतिरिक्त किट मंगाए हैं। एक अधिकारी ने कहा, 'छह स्थानों पर रोज 1,500 से अधिक लोगों की जांच की क्षमता है। राज्य में निजी लैब रोज 600 से 700 जांच कर सकती हैं। अभी रोज 600 से 700 लोगों की जांच की जा रही है।'

पश्चिम बंगाल सरकार इस बारे में ज्यादा कुछ कहने को तैयार नहीं हैं। राज्य में ऐसे सात इलाकों की पहचान की गई है जहां त्वरित जांच की जाएगी। राज्य में एनएबीएल से मान्यता प्राप्त 30 लैब यह काम करेंगी।

(साथ में वीरेंद्र सिंह रावत, दशरथ रेड्डी, गिरीश बाबू, समरीन अहमद, विनय उमरजी, अभिषेक रक्षित और सोहिनी दास)

- भारत में रोजाना करीब 20,000 नमूनों की जांच हो रही है और अगले कुछ हफ्तों में इसे 100,000 तक पहुंचाने की योजना
- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने राज्यों को त्वरित स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रकिया तेज करने की सलाह दी
- महाराष्ट्र में पीपीई किट की कमी है, इसलिए बीएमसी ने हर हफ्ते 35,000 पीपीई किट खरीदने की योजना बनाई

लॉकडाउन बढ़ाने पर क्या है प्रमुख राज्यों की राय

तमिलनाडु
- चिकित्सा विशेषज्ञों की समिति ने लॉकडाउन दो हफ्ते तक बढ़ाने की सिफारिश की है। कैबिनेट शनिवार को फैसला करेगी।

केरल
- एक कार्यबल ने जिला दर जिला तीन चरणों में लॉकडाउन हटाने की सिफारिश की है। कुछ जिलों में लॉकडाउन हट सकता है। तिरुवनंतपुरम में एक हफ्ते में कोई मामला नहीं आया।

कर्नाटक
- राज्य मंत्रिमंडल ने विशेषज्ञ पैनल की सिफारिश टालते हुए 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रखने की बात कही है। प्रधानमंत्री की बैठक के बाद फैसला होगा।

तेलंगाना
- मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के समर्थन में हैं। उन्होंने इस हफ्ते कहा था, 'हम आर्थिक समस्या से उबर सकते हैं लेकिलोगों की जान की भरपाई नहीं हो सकती।'

गोवा
- मंत्रिमंडल की बैठक में लॉकडाउन बढ़ाने और राज्य की सीमाओं को 30 अप्रैल तक सील करने की सिफारिश।

महाराष्ट्र
- देश के कुल मामले में करीब 17 फीसदी राज्य में हैं। इनमें से आधे मामले मुंबई के हैं। सरकार शहरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, जहां लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है।

ओडिशा
- राज्य ने लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाया

पंजाब
- राज्य में लॉकडाउन 1 मई तक बढ़ाने का फैसला। लेकिन फसलों की कटाई और खरीद के लिए विशेष इंतजाम।

छत्तीसगढ़
- राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में।

उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान
- इन राज्यों ने भी लॉकडाउन बढ़ाने पर सहमति जताई। इनमें फसल कटाई और अनाज खरीद के लिए इंतजाम।

पश्चिम बंगाल
- मुख्यमंत्री ने चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने के संकेत दिए।

राज्यों का दबाव, केंद्र को करना है फैसला

पृष्ठ 1 का शेष

उन्होंने कहा कि कई मुख्यमंत्रियों ने 2 अप्रैल को पहली बैठक में प्रधानमंत्री से कहा था कि वायरस से लड़ने के लिए कम से कम 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपये की जरूरत होगी। शनिवार की बैठक में केंद्र राज्यों को कुछ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने के लिए कह सकता है जबकि राज्य केंद्र से ज्यादा फंड की मांग कर सकते हैं।

वायरस के प्रसार के आकलन और अनुमानों के बारे में भी केंद्र और राज्यों के बीच सहमति नहीं है। सिंह ने कहा कि राज्य में इसका सामुदायिक प्रसार शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों ने उनसे कहा है कि वायरस का संक्रमण अगस्त में चरम पर पहुंचेगा और इससे पंजाब की 87 फीसदी और देश की 58 फीसदी आबादी संक्रमित होगी। बाद में स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने इस बात पर असहमति जताई कि देश में कोविड-19 का संक्रमण सामुदायिक प्रसार के दौर में पहुंच गया है। साथ ही वह सिंह के अनुमानों से भी सहमत नहीं थे।

ज्यादातर राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है

केंद्र कुछ आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना चाहता है लेकिन इसके लिए उसे राज्यों को भी मनाना होगा। राज्य सरकारों के सूत्रों का कहना है कि अगर केंद्र राज्यों के वित्तीय बोझ को साझा करे तो ऐसा हो सकता है। माकपा के नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि केरल केंद्र से राज्यों को मिलने वाली अपर्याप्त फंडिंग का मामला उठाएगा।

फल-सब्जी की आवक पर असर

पृष्ठ 1 का शेष

केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से कहा है कि किसानों को मंडियों के बजाय सीधे व्यापारियों को माल बेचने की इजाजत मिलनी चाहिए। वे ऐसे कारोबारियों को भी अपनी उपज बेच सकते हैं, जिनके पास सीधे किसानों से खरीद करने के लिए लाइसेंस या पंजीकरण भी नहीं है। लेकिन हफ्ता बीतने के बाद भी किसी राज्य ने ऐसा नहीं किया।

जहां तक अनाज और दलहन का सवाल है तो रबी फसल की कटाई चल रही है और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में तो कटाई पूरी हो चुकी है। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि लॉकडाउन के कारण नकदी की कमी एक बड़ी चुनौती है, जिसके कारण वे गर्मियों में बुआई के लिए बीज और उर्वरक नहीं खरीद पा रहे हैं। उन्होंने आशंका जताई कि यह स्थिति जून में शुरू होने वाली खरीफ की अगली बुआई तक जारी रह सकती है।

मध्य प्रदेश के युवा किसान नेता भगवान मीणा ने कहा कि लॉकडाउन से पहले ही राज्य की कई मंडियों में चने और सरसों की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से 20 से 30 फीसदी कम चल रही थी। मंडियां खुलने से आवक एकाएक बढ़ेगी, जिससे कीमतों में भारी कमी आएगी।

कंसोर्टियम ऑफ इंडियन फार्मर्स एसोसिएशंस के सलाहकार पी चेंगल रेड्डी ने कहा कि मजदूरों की कमी खरीफ की बुआई

चेन्नई के कोयंबेडू थोक बाजार में प्याज की बोरियां उतारते मजदूर *पीटीआई*

तक जारी रह सकती है क्योंकि प्रवासी मजदूर अगले कुछ साल तक अनिश्चितता की ऐसी स्थिति का सामना करने को तैयार नहीं होंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को अनाज की तरह फल के मामले में भी ढुलाई के लिए मुख्य उत्पादक राज्यों में रेलवे के डिब्बे मुहैया कराने चाहिए।

मंडियां बंद होने, मजदूरों और परिवहन की कमी होने तथा किसानों की बदहाली ने एक बार फिर कृषि विपणन में सुधारों की जरूरत को सुर्खियों में ला दिया है। क्रेडिट सुइस में इक्विटी रिसर्च के प्रबंध निदेशक नीलकंठ मिश्रा ने कहा कि इस स्थिति को सुधारों के लिए एक अवसर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि नियमित कृषि बाजारों ने अपनी उपयोगिता खो दी है, जिससे समानांतर माध्यम उभर रहे हैं। कुछ राज्य बड़ी ग्रॉसरी चेनों और ई-कॉमर्स कंपनियों को सीधे किसानों से खरीद के लिए अस्थायी अनुमति दे रहे हैं। किसानों को भी उपभोक्ताओं को सीधी बिक्री की इजाजत दी जा रही है। लॉकडाउन के बाद भी ऐसा ही रहा तो मंडियों का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। कई लोग किसानों की बदहाली के लिए इन्हीं मंडियों को जिम्मेदार मानते हैं।

कृषि विपणन में लंबे समय से सुधारों की जरूरत महसूस की जा रही है। केंद्र ने इसके लिए आदर्श एपीएमसी कानून भी बनाया। राज्यों ने भी इलेक्ट्रॉनिक नैशनवाइड एग्रीकल्चर मंडी (ईनाम) प्लेटफॉर्म के जरिये इसे लागू करने पर सहमति जताई है। लेकिन इसकी चाल बहुत धीमी है। जाने माने कृषि कारोबार विशेषज्ञ विजय सरदाना ने कहा कि अब समय आ गया है कि किसानों के पास अपनी उपज बेचने के लिए एपीएमसी के साथ-साथ एक वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए। एपीएमसी काम करना जारी रख सकती हैं लेकिन किसानों से सीधी खरीद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

देश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 6,761 पर पहुंचा

रुचिका चित्रवंशी

देश में कोरोनावायरस संक्रमण से मरने वालों की तादाद 200 के आंकड़े पार कर चुकी है जिनमें से करीब आधी मौत महाराष्ट्र में हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमित लोगों की तादाद 6,761 तक पहुंच चुकी है। पिछले एक दिन में 33 लोगों की मौत हो गई है। देश में लॉकडाउन के तीसरे हफ्ते के बावजूद पिछले दिन से अब तक संक्रमण के 678 नए मामले सामने आए हैं।

अभी तक देश भर में कोरोनावायरस के संक्रमित मरीजों की अधिकतम संख्या महाराष्ट्र में 1,364 रही जबकि उसके बाद दिल्ली में 898 मामलों की पुष्टि की गई है। शुक्रवार तक कोरोनावायरस से हुई मौत का आंकड़ा 206 तक पहुंच गया, जिनमें से 97 मौत महाराष्ट्र में हुई है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार केवल मुंबई में ही 54 लोगों की मौत हुई है।

सरकार ने गुरुवार को अपनी संक्रमण जांच की रणनीति में संशोधन करते हुए कहा कि संक्रमण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी व्यक्ति को अगर सर्दी, खांसी या बुखार के लक्षण दिखते हैं तो उनकी जांच की जाएगी। एक दिन में कोरोनावायरस संक्रमण से जुड़े 16,000 टेस्ट किए गए जिनमें से महज 0.2 फीसदी संक्रमण मामले की ही पुष्टि हो पाई। पिछले हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक विश्लेषण साझा किया था जिसमें स्त्री-पुरुष के हिसाब से संक्रमण के मामले का जायजा लेने पर यह अंदाजा मिला कि पुरुषों में संक्रमण की दर सबसे ज्यादा है। कोरोनावायरस से संक्रमित पुरुष मरीजों की तादाद 76 फीसदी रही जबकि महिला मरीजों की तादाद 24 फीसदी तक थी। वायरस के प्रकोप से मरने वालों में भी 73 फीसदी पुरुष ही थे। सरकार ने इस बात से इनकार किया है कि देश में कोरोनावायरस का प्रसार सामुदायिक स्तर पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाताओं से कहा, 'अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हम लोग सबसे पहले इस बात की जानकारी देंगे ताकि हम सभी ज्यादा सतर्क रह सकें।'

एक मरीज की जांच करता चिकित्साकर्मी *पीटीआई*

जिन मामलों में संक्रमित मरीजों का कहीं यात्रा करने या किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने का कोई सूत्र नहीं मिलता, उनके बारे में अग्रवाल ने कहा, 'इसके लिए आगे की जांच की आवश्यकता है। अभी तक कोई सामुदायिक स्तर पर इसका कोई प्रसार नहीं हो रहा है।' सरकार कोरोना संकट के बीच ब्लड बैंकों को दिशा-निर्देश भी दे रही है ताकि सुरक्षा के साथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की गतिविधियों को बढ़ाया जा सके। अग्रवाल ने यह भी आश्वासन दिया कि देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की पर्याप्त आपूर्ति है जिसका इस्तेमाल स्वास्थ्यकर्मियों और संक्रमित लोगों के संपर्क में रहकर जोखिम उठा रहे लोगों के लिए रोगनिरोधी दवा के रूप में किया जाएगा। सरकार ने अनुमान लगाया है कि फिलहाल देश में इसके 3.28 करोड़ से ज्यादा टैबलेट हैं और महज 1 करोड़ टैबलेट की आवश्यकता पड़ सकती है।

अग्रवाल ने कहा, 'हम जितनी जरूरत है उसके मुकाबले तीन गुना टैबलेट की आपूर्ति की जा सकती है। हम भविष्य की मांग के लिए भी आपूर्ति के लिए करार कर रहे हैं।'

कोरोना के आंकड़े
- संक्रमण के **678** नए मामले सामने आए
- संक्रमितों की अधिकतम संख्या महाराष्ट्र में **1,364** रही
- दिल्ली में अब तक **898** मामलों की पुष्टि हुई
- देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के **3.28** करोड़ से ज्यादा टैबलेट उपलब्ध
- लेकिन रोगनिरोधी दवा के तौर पर महज **1** करोड़ टैबलेट की पड़ेगी जरूरत
- सरकार का दावा सामुदायिक स्तर पर नहीं बढ़ रहा है संक्रमण